नई सोच • नई शुरूआत • नया भारत

अनप्लग इंडिया

सच की आवाज, भारत की पहचान

नोएडा एनसीआर संस्करण

वर्ष : 01 | अंक : 34 | नोएडा, मंगलवार, 3 नवम्बर, 2026 | Website: www.unplugindia.com | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 03 रुपए

आज का विचार

‘किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जितना पढ़ोगे, उतना बढ़ोगे। ‘



संक्षिप्त समाचार

चारधाम में हेली सेवाओं पर ब्रेक, केदारनाथ शटल जारी रहेगी

- 11 ऑपरेटरों के विरोध के बाद फैसला, अगले सीजन में शुरू होंगी चार्टर उड़ानें, रिफंड होंगे रुपए

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में चारधाम की चार्टर हेली सेवाओं पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। 11 हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के दो पायलट अनिवार्य करने के नियम के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। सोमवार को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और



नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के बीच हुई बैठक में तय किया गया कि चार्टर हेली सेवाएं अब अगले सीजन में ही शुरू होंगी। हालांकि, केदारनाथ में शटल हेली सेवा जारी रहेगी। एजेंसी के सीईओ प्रतीक जैन ने बताया कि इस सीजन में चार्टर हेली सेवाओं की ज्यादा बुकिंग नहीं हुई थी। जिन यात्रियों ने बुकिंग कराई थी, उन्हें पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। केदारनाथ में सामान्य शटल हेली सेवाओं का संचालन जारी है। यहां एजेंसी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कंट्रोल रूम बनाया है। यहां से मौसम और उड़ानों की पल-पल की जानकारी के आधार पर हेलीकॉप्टरों को उड़ान की अनुमति दी जा रही है। हालांकि, नए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने के कारण लंबी दूरी की पर्सनल चार्टर सेवाएं बंद हैं। वहीं, गंगोत्री के कपाट 10 नवंबर, केदारनाथ और यमुनोत्री के 11 नवंबर, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 16 नवंबर को बंद होंगे।

एएपी छोड़ने वाले तीनों विधायक बीजेपी में शामिल

- तीनों ने पिछले दो दिन में इस्तीफा दिया, बीजेपी के हुए

अमृतसर (एजेंसी)। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें अमृतसर नॉर्थ से कुंवर विजय प्रताप सिंह, समाना से चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर से हरमीत सिंह



पठानमाजरा शामिल हैं। बीजेपी जॉइन करने के बाद विधायक कुंवर ने कहा कि पंजाब में गैंगस्टर सरकार का हिस्सा बन गए हैं। फिरौती की इंडस्ट्री चल रही है। इन तीनों विधायकों ने पिछले 2 दिनों में एएपी से इस्तीफा दिया। रविवार को जौड़ामाजरा और पठानमाजरा के इस्तीफे के बाद सोमवार को कुंवर ने भी पार्टी छोड़ दी। कुंवर और पठानमाजरा ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। कुंवर को जून 2025 में एएपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था।

आठ नए युद्धपोत से लैस होगी अपनी नौसेना

- 53,866 करोड़ रुपये होगा खर्च, रक्षा मंत्रालय ने किया करार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए देश में आठ अत्याधुनिक अगली पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोत बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने इन युद्धपोतों के निर्माण और खरीद के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ कुल 53,866.50 करोड़ रुपए के करार किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस करार को लेकर खुशी जाहिर की है। 2 नवंबर को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इन करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इन अगली पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों में आधुनिक मिसाइलों, हथियारों और सेंसर प्रणालियों से लैस अत्याधुनिक क्षमताएं होंगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि इन जहाजों के निर्माण से अगले दस वर्षों में शिपयार्डों में लगभग 72 लाख पर्सन-डे और सहायक उद्योगों तथा कंपनी में 460 लाख पर्सन-डे के बराबर रोजगार पैदा होगा।



भारतीय नौसेना को मिली ताकत

इन युद्धपोत की मदद से नौसेना हवा, समुद्र की सतह और समुद्र के भीतर मौजूद खतरों से निपट सकेगी। इन युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से उसकी अभियान क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। ये समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने और पनडुब्बियों का पता लगाकर उनसे मुकाबला करने जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में भूमिका निभाएंगे। ये युद्धपोत तटीय सुरक्षा मजबूत करने, समुद्र के किनारे उथले इलाकों में सैन्य अभियान चलाने और समुद्री क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने में भी मदद करेंगे। इनकी तैनाती से भारतीय नौसेना की समुद्र में मौजूदगी और निगरानी क्षमता को मजबूती मिलेगी। प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए निर्माण कंपनियों का चयन किया गया है। यह पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें भारतीय नौसेना के स्वदेशी डिजाइन पर आधारित युद्धपोतों का निर्माण रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।

कोलकाता स्थित जीआरएसई पांच युद्धपोतों का तैयार करेगी डिजाइन

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस परियोजना के तहत कोलकाता स्थित जीआरएसई पांच युद्धपोतों का निर्माण करेगा। वहीं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए तीन युद्धपोत बनाएगा। खास बात यह है कि इन सभी युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना खुद तैयार करेगी। इनका निर्माण देश के रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम करेंगे। इस परियोजना का फायदा केवल नौसेना की युद्धक क्षमता तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देश के स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। परियोजना में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निजी शिपयार्ड, भारतीय औद्योगिक साझेदारों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भी भागीदारी होगी।

राहुल गांधी के खेमे में असुरक्षा का माहौल

- कांग्रेस में प्रियंका गांधी को अलग-थलग करने की कोशिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर दरार आ गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी के बढ़ते प्रभाव की वजह से राहुल गांधी खेमे में असुरक्षा दिख रही है और प्रियंका गांधी को पार्टी में अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया ब्लॉक की आयोजित रैली में प्रियंका गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। शनिवार को आयोजित सांकेतिक संसद की कार्यवाही में भी प्रियंका गांधी को अलग थलग करने की कोशिश की गई। जारी वीडियो मैसेज में प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस दो शक्ति केंद्रों में बंट चुकी है।



सीआईएसएफ ने सुरक्षा देने का 56 साल पुराना स्ट्रक्चर बदला

- अब पावर-स्टील प्लांट और बंदरगाह के लिए अलग-अलग सेक्टर, पहले जोन वाइज था

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। फोर्स ने आज से अपने 56 साल पुराने टेरिटोरियल कमांड मॉडल को खत्म करके फंक्शनल सेक्टर मॉडल अपना लिया है। फोर्स अब तक जोन के हिसाब से काम करती थी। जैसे - मुंबई जोन के एक ही अधिकारी के पास पावर प्लांट भी होता था और कोयला खदान भी। इससे सुरक्षा मिली-जुली रहती थी। नए मॉडल में एक जैसी इंडस्ट्रियल यूनिट को एक ही छतरी के नीचे लाया गया है। यानी देशभर के सारे पावर प्लांट, सारे स्टील प्लांट, सारे बंदरगाह अलग-अलग डेडिकेटेड सेक्टर के अधीन होंगे।



सीआईएसएफ का दावा- काम अलग तो सुरक्षा भी अलग हो

अब तक सीआईएसएफ के फील्ड और प्रशासनिक ठिकाने जोनल आधार पर बने थे। इस वजह से एक ही फील्ड फॉर्मेशन अलग-अलग क्षेत्रों में बनी औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा संभालता था। उदाहरण के लिए, किसी फील्ड फॉर्मेशन के पास बिजली और कोयला क्षेत्र की इकाइयों की जिम्मेदारी एक साथ होती थी। सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ इकाइयां इसका अपवाद थीं।

फिर ट्रेन से कटा युवक, भोपाल में पटरी पर मिली लाश

मां-पत्नी और 2 बच्चों की गला काटकर हत्या

पुलिस घर पहुंची तब खुला हत्याकांड, कर्ज में डूबा था

भोपाल (एजेंसी)। भोपाल के मालीखेड़ी में सोमवार को असिस्टेंट लोको पायलट के किराए के घर में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश मिली है। सभी के गले कटे हुए थे। वहीं, घर के बेटे की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। शक है कि युवक ने पहले सभी की हत्या की, इसके बाद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। छोला पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में परिवार के मुखिया पर कर्ज का दबाव था। घर में नरेंद्र की मां सरस्वती साहू (50), पत्नी सोमलता साहू (29), बेटी कृति साहू (10) और बेटे खुश



साहू (6) के शव मिले। सभी के सिर और गले पर चोट के निशान मिले हैं। एसीपी निशातपुरा शशांक जैन के मुताबिक, पुलिस को नरेंद्र के घर से निकलने का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें वह सुबह करीब 7.30 से 8 बजे के बीच घर से निकलता दिखाई दे रहा है। शक है कि सुबह-सुबह वारदात हुई है।

रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश मिली, तब खुला मामला

परिवार के मुखिया नरेंद्र साहू (35) का शव सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला था। सोमवार सुबह परिवार के एक रिश्तेदार को नरेंद्र की मौत की सूचना मिली। वह परिजन को जानकारी देने मालीखेड़ी स्थित घर पहुंचा, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। फोन पर भी किसी से संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर घर में प्रवेश किया तो अंदर चार लोगों के शव मिले।

संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत शामिल, आगामी कार्ययोजना पर होगा मंथन

इंदौर में आरएसएस की तीन दिनी बैठक का आगाज

- 408 पदाधिकारी संगठन विस्तार-सामाजिक अभियानों की समीक्षा करेंगे

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक सोमवार को डेली कॉलेज में शुरूहो गई। बैठक में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और सभी छह सह सरकार्यवाह सहित देशभर के करीब 408 प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं। 4 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान हुए कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ संगठन विस्तार और आगामी कार्ययोजना पर मंथन होगा। संघ ने पिछले एक साल में देशभर में 13 हजार से अधिक नई दैनिक शाखाएं जुड़ने की जानकारी दी है। इसके साथ ही 65 हजार से ज्यादा हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। बैठक में इन आयोजनों से मिले अनुभवों के आधार पर आगे की गतिविधियों की दिशा तय की जाएगी। अखिल



भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि बैठक में संघ के 11 क्षेत्र और 46 प्रांतों से संघचालक, सह संघचालक, कार्यवाह, सह कार्यवाह, प्रचारक और सह प्रचारक शामिल हुए हैं। अंतिम दिन विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी और आंकड़े साझा किए जाएंगे।

65 हजार से ज्यादा हिंदू सम्मेलन आयोजित

शताब्दी वर्ष के दौरान देशभर में 65 हजार 660 हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया। आंबेकर के मुताबिक, शहरों में बस्ती स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ-दस गांवों को मिलाकर बनाए गए मंडल स्तर पर ये सम्मेलन हुए। कई जगह दो-तीन मंडलों को मिलाकर भी आयोजन किए गए। उन्होंने बताया कि इन सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और समाज की ओर से समर्थन मिला। लोगों ने संघ की शाखाओं से जुड़ने की इच्छा जताई। सामाजिक संस्थाओं और संगठनों ने भी अपने कार्यक्रमों में स्वयंसेवकों के अनुभवों का सहयोग लेने की इच्छा व्यक्त की है। बैठक में इन सम्मेलनों से मिले अनुभवों और सामाजिक सहभागिता की समीक्षा होगी। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी भी रही। अब इस अनुभव के आधार पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों और उपक्रमों पर विचार किया जाएगा।

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरुकता अभियान

संघ की पिछली दो-तीन बैठकों में नशीली दवाओं के बढ़ते चलन पर चिंता जताई गई है। इस बार भी यह विषय एजेंडे में शामिल रहेगा। आंबेकर ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर प्रयास जरूरी हैं। युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रखने के लिए जागरुकता अभियान चलाने पर विचार होगा।

एमपी में शराब तस्करों ने टीआई को कुचला, मौत

- इंदौर-बैतूल हाईवे पर तस्करी रोकने गए थे टीआई दिलीप पुरी

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के देवास में अवैध शराब भरे वाहन (ट्रक) ने खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल पुरी को अस्पताल ले जाया गया। यहां करीब दो घंटे तक इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुरी रविवार रात करीब डेढ़ बजे अवैध शराब की तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने टीम के साथ इंदौर-बैतूल हाईवे पहुंचे थे। नेमावर पुलिस भी इसी ट्रक का पीछा कर रही थी। पुलिस टीम को ट्रक डिवाइडर के किनारे खड़ा मिला। पुरी ने ट्रक ड्राइवर से बाहर आने को कहा तो वो ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ाकर आगे बढ़ाने लगा। इस दौरान पिछला पहिए पुरी के ऊपर चढ़ गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीआई पुरी की पत्नी को एसआई पद पर अनुकंपा नियुक्ति और परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।



पीएम-कुसुम स्कीम से 30 लाख से ज्यादा किसानों को हुआ फायदा, सोलर पंप से सालाना एक लाख रुपए की हो रही बचत : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पीएम-कुसुम स्कीम से देशभर में 30 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है और इस योजना के माध्यम से हर किसान सोलर पंप से एक लाख रुपए की सालाना बचत कर पा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन'को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज प्रगति की है और उद्योगों, खेतों तथा घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'देश भर के किसान पीएम-कुसुम योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस पहल के जरिए, 30 लाख से ज्यादा किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अनुमान है कि सोलर पंपों का इस्तेमाल करके हर किसान सालाना लगभग 1 लाख रुपए की बचत कर पा रहा है। '

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने के लिए सभी सरकारी इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और स्ट्रीट-लाइटिंग सिस्टम को सौर ऊर्जा से जोड़ना है।

उन्होंने कहा, 'पिछले 12 वर्षों में, हमने



उद्योगों और खेतों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम किया है। पूरे भारत में 44,000 से अधिक सरकारी इमारतें अब सौर ऊर्जा से जुड़ी हैं, जिससे सालाना लगभग 700 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। '

प्रधानमंत्री ने 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत हुई प्रगति का भी जिक्र किया। फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है।

उन्होंने कहा, 'पिछले 24-25 महीनों में 65 लाख से अधिक परिवार इस पहल से जुड़े हैं। '

वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश ने 2025 में ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि पेरिस समझौते के तहत तय समय-सीमा से पांच साल पहले ही हासिल कर ली गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'पेरिस समझौते के तहत, भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा करने का संकल्प लिया था। हमने 2025 में ही, तय समय से पांच साल पहले, इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। आज, भारत की स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। '



वाहनों पर जारी सख्ती में ढील देने से इनकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी में वाहनों के प्रवेश को लेकर जारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस स्तर पर अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। याचिका में 23 जून 2026 की एक अधिसूचना के एक विशेष प्रावधान चुनौती दी गई है, जिसमें पर्यावरण एवं वन विभाग दिल्ली सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया है। याचिका के अनुसार यह निर्देश कहता है कि एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत व बीएस-6 श्रेणी से नीचे के वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि यह रोक हर साल 1 नवंबर से अपने आप लागू हो जाती है। याचिकाकर्ता ने इस रोक को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह दूसरी गाड़ियों के साथ उनके पंजीकरण की जगह के आधार पर अलग तरह से बर्ताव करता है। याचिका में तीन महीने की पूरी रोक की अधिसूचना पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह किसी खास दिन वायु गुणवत्ता इंडेक्स की परवाह किए बिना लागू होता है।

आईपीयू ने पीएचडी में शुरू की प्रवेश प्रक्रिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपीयू) ने पीएच.डी. कार्यक्रम (शीतकालीन सत्र)-2026-27 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान ने शीतकालीन सत्र के लिए पीएच.डी. कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों में आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये विषयमॉस कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिकी, शिक्षा, केमिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेज, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंटल साइंस, लॉ एंड लीगल स्टडीज, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र के साथ-साथ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। पात्रता मानदंड, प्रवेश प्रक्रिया, अनुसंधान क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट द्वश्वह्व.ड्डष्ठ्वद्व पर उपलब्ध हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि (ऑनलाइन) 25 नवंबर शाम 5:30 बजे तक है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा (पीईटी) की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट द्वश्वह्व.ड्डष्ठ्वद्व पर जारी अधिसूचनाओं से स्वयं को अपडेट रखें।पात्र, पूर्णकालिक पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए पीएच.डी. रिसर्च फेलोशिप उपलब्ध हैं।

ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर विचार से इनकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने एक आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दिल्ली की अदालत ने चंद्रशेखर को इस मामले में आठ साल की जेल की सजा सुनाई थी और उसके कृत्य को 'संस्थागत पवित्रता का उल्लंघन' करार दिया था। दिल्ली की एक अदालत ने 20 अगस्त को चंद्रशेखर को दोषी ठहराया था। उस पर आरोप था कि उसने 2017 के एक भ्रष्टाचार मामले में जमानत दिलाने के लिए एक विशेष जज को प्रभावित करने के उद्देश्य से खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताया था। 29 अगस्त को अदालत ने उसे इस मामले में आठ साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद चंद्रशेखर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने के लिए कोई आधार नहीं बनता है।

सेंट्रल पार्क में दो दिन आयोजित होगा ड्रोन शो

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार बीते वर्ष की तरह इस बार भी दीवापली पर ड्रोन एवं लाइट शो का आयोजन करने जा रही है। इस बार यह शो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सेंट्रल पार्क को सजाया जाएगा और वहां ड्रोन शो के जरिये लोगों को मनमोहक दृश्य दिखाया जाएगा। यह आयोजन आगामी 6 और 7 नवंबर की शाम को किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार बीते वर्ष दिल्ली सरकार द्वारी दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन इंडिया गेट पर किया गया था। इसमें न केवल दीये जलाकर इंडिया गेट के पास रोशनी की गई थी बल्कि वहां ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया था। इस वर्ष यह आयोजन दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वह स्वयं कैबिनेट मंत्रियों के साथ शामिल होंगी। इस बार भी दिये जलाकर सेंट्रल पार्क को जगमग किया जाएगा और यहां आने वाले लोगों के लिए ड्रोन शो का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा दिल्ली में विभिन्न जगहों पर उचित लाइट की व्यवस्था कर दिल्ली को जगमग किया जाएगा ताकि त्योहार के समय दिल्ली में भरपूर रोशनी रहे।

बुधवार से 'यमुना सफारी' का आनंद ले सकेंगे नागरिक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में यमुना पर चलने वाली क्रूज सेवा को आगामी बुधवार से शुरु किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यमुना में क्रूज परिचालन को लेकर चल रहा ट्रायल पूरा हो चुका है। इसलिए बुधवार से इस क्रूज पर दिल्लीवासियों के लिए यमुना सफारी शुरु की जाएगी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में क्रूज की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा किराये को लेकर भविष्य में समीक्षा भी की जाएगी ताकि ज्यादा यात्री क्रूज की सवारी का आनंद ले सकें। जानकारी के अनुसार बीते सप्ताह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी पर विकसित की जा रही क्रूज सेवा का ट्रायल लिया था। इसके बाद से एक सप्ताह का ट्रायल यमुना में शुरु किया गया था जो पूरा हो गया है। ट्रायल के दौरान यमुना में क्रूज का परिचालन सामान्य रहा जिसके चलते अब आम लोगों के लिए इस सेवा को शुरु किया जा रहा है। बुधवार से दिल्ली में रहने वाले आम लोग इस क्रूज से सफर कर सकेंगे। एक बारी में इस क्रूज पर लगभग 40 लोग सफर कर सकते हैं और इसका किराया अभी 500 रुपये प्रति सवारी रखा गया है। लेकिन भविष्य में इसकी समीक्षा कर किराये को कम किया जा सकता है।

पर्यटन और स्थानीय सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली सरकार के अनुसार यह पहल एक आकर्षक पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोनिया विहार से जगतपुर तक लगभग छह किलोमीटर के जलमार्ग पर विकसित की गई यह क्रूज सेवा दिल्ली में पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नदी के आसपास उपलब्ध सुविधाओं को विकसित करके इस क्षेत्र को एक आकर्षक पर्यटन एवं मनोरंजन स्थल बनाया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधा के लिए फूड कियोस्क, रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए किड्स ज़ोन और अन्य आवश्यक जनसुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

45 मिनट का होगा क्रूज का सफर

अधिकारियों के अनुसार 40 यात्रियों की क्षमता वाली क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर स्थित शनि मंदिर तक आने-जाने का पूरा सफर लगभग 35 से 45 मिनट में पूरा करेगी। यात्रियों के लिए तैयार की गई व्यवस्था के अंतर्गत परिसर में प्रवेश शुल्क 50 रुपये और क्रूज की एक पूरी यात्रा का प्रस्तावित शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार, डीडीए, दिल्ली सरकार और दिल्ली पर्यटन के साझा प्रयासों से यह परियोजना साकार हो रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी का आदेश रद्द किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी से जुड़े उन मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था, जिनमें फैसले सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन दो महीने के भीतर नहीं सुनाए गए थे। न्यायमूर्ति सीकरी को जुलाई 1999 में दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। हाल ही में दिए एक फैसले में न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि हालांकि समय पर फैसले आना निश्चित रूप से जनहित का विषय है, लेकिन सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत केवल वही जानकारी मांगी जा सकती है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद हो।

दिल्ली में पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन, पुलिस मुख्यालय के बाहर सड़क पर बैठे

-एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और एसएचओ अरुण कुमार की बहाली की मांग

-पुलिस आयुक्त के साथ करीब 40 मिनट चली बैठक के बाद भी नहीं थमा विरोध

नई दिल्ली, एजेंसी।

नई दिल्ली, 02 नवंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के शाहदरा थाने में पुलिसकर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद दो पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर सोमवार को पुलिस विभाग में असंतोष सामने आया। तबादले के विरोध में करीब 100 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल रहीं। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने तीन प्रमुख मांगें रखते हुए आरोपी अधिवक्ता की गिरफ्तारी, थाने में अधिवक्ताओं के प्रवेश को नियंत्रित करने और कचहरी जाने वाले पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

पुलिसकर्मियों ने रखीं ये तीन प्रमुख मांगें

प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों की पहली मांग है कि पुलिसकर्मियों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने और उन्हें धमकी देने वाले अधिवक्ता को गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दूसरी मांग के तहत पुलिसकर्मियों ने कहा कि किसी भी थाने में थाना प्रभारी के कक्ष में एक समय पर 5 से अधिक अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि इससे थाने के भीतर अनावश्यक भीड़ और विवाद की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तीसरी मांग कचहरी जाने वाले पुलिसकर्मियों की सुरक्षा से संबंधित है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि न्यायालय परिसर में ड्यूटी अथवा अन्य कार्यों से जाने वाले पुलिसकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

एसीपी और थाना प्रभारी की बहाली की मांग

प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों ने सहायक पुलिस आयुक्त मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार को उनकी पूर्व तैनाती पर वापस भेजने की मांग भी उठाई। पुलिसकर्मियों का कहना है कि विवाद के बाद दोनों अधिकारियों का तबादला किया जाना उचित नहीं है और उनकी बहाली पर विचार किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने और विभाग के भीतर संवाद की व्यवस्था मजबूत करने की अपील की।

23 अक्तूबर को थाने में हुई थी झड़प

दरअसल, पूरे विवाद की शुरुआत 23 अक्तूबर को शाहदरा थाने के भीतर पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प से हुई थी। इस घटना में अधिवक्ता ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट आई थी। घटना के बाद पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके विरोध में जिला अदालत के अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। वकीलों की हड़ताल और विरोध के बीच दिल्ली पुलिस ने 28 अक्तूबर





को सहायक पुलिस आयुक्त मनस्वी वशिष्ठ का तबादला गांधी नगर के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी पद से विशेष पुलिस इकाई महिला एवं बाल में कर दिया। वहीं, शाहदरा थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार को भी उनके पद से हटाकर सुरक्षा इकाई में भेज दिया गया। दोनों अधिकारियों के तबादले के बाद अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी।

एसीपी वशिष्ठ ने बताया स्वाभाविक विरोध

एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने प्रदर्शन को स्वाभाविक रूप से सामने आया विरोध बताते हुए कहा कि वह भी इसमें शामिल हो रही हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिसकर्मियों की समस्याओं और शिकायतों को रखने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उन्होंने औपचारिक आवेदन भी दिया।

वशिष्ठ ने कहा कि पुलिस थानों के भीतर हो रही अराजकता और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता फैलाते हैं। ऐसे तत्व केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदायक हैं।

उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ सीधे संवाद आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। उनका सुझाव था कि इस संवाद का सीधा प्रसारण किया जाए, ताकि पुलिसकर्मी और आम नागरिक भी अधिकारियों के सामने रखी जाने वाली समस्याओं और उनके जवाबों को सुन सकें।

पुलिस आयुक्त के साथ करीब 40 मिनट चली बातचीत

प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त ने प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को बातचीत के लिए आदर्श सभागार में बुलाया। वहां पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं और उनकी मांगें सुनीं। पुलिस आयुक्त और प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई।

हालांकि, बैठक के बाद पुलिसकर्मी पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे। एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने पुलिस आयुक्त के सामने 5 मांगें रखीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के अनुसार उन्हें तत्काल कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिसकर्मी सभागार से बाहर आ गए और दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को फिर से सभागार में बुलाया और उनके साथ बातचीत शुरू की।

वीडियो जारी कर मुख्यालय पहुंचने की अपील

इससे पहले गांधी नगर की एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने एक वीडियो संदेश जारी कर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से सोमवार सुबह 8 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी पुलिस आयुक्त के सामने अपनी बात रख सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी अथवा अन्य व्यस्तताओं के कारण व्यक्तिगत रूप से मुख्यालय नहीं पहुंच सकते, वे दृश्य संवाद के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन के बाद अब पुलिसकर्मियों की मांगों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के परिणाम पर सबकी नजरें टिकी हैं।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर नहीं बनेंगे टोल प्लाजा, गेंट्री पोल्स से कटेगा टैक्स

नई दिल्ली, एजेंसी।

देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा बनाने की पारंपरिक प्रथा अब समाप्त होने जा रही। भविष्य में बनने वाले और वर्तमान में निर्माणाधीन 55,000 किलोमीटर से अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब टोल प्लाजा के स्थान पर आधुनिक गेंट्री पोल्स और ओवरहेड सेंसर्स लगाए जाएंगे। इस नई व्यवस्था से वाहन चालक बिना रफ्तार धीमी किए सामान्य गति से टोल पार कर सकेंगे, जिससे राजमार्गों पर लगने वाले लंबे जाम और बूम-बैरियर की कतारों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 अक्तूबर को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है।? मंत्रालय के इस नए परिपत्र के दायरे में देश भर के 35,000 किलोमीटर निर्माणधीन व प्रस्तावित 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल किए गए हैं। इस तकनीक में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों व फास्टैग स्कैनर्स के जरिए टोल की राशि सीधे खाते से कट जाएगी। विदित हो कि सरकार ने देश के मौजूदा और पहले से चालू राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) यानी सैटेलाइट आधारित टोलिंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का लक्ष्य वर्ष 2028-2029 निर्धारित किया गया है। 7 एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह आधुनिक मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) और गेंट्री-आधारित टोलिंग विन्यास उन सभी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड चौड़ीकरण परियोजनाओं पर लागू होगा, जो वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं या जिनकी योजना तैयार की जा चुकी है। इसमें उत्तर भारत विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड को जोड़ने वाले चुनिंदा परियोजनाएं शामिल हैं।

दूरी के अनुसार टोल भुगतान जितना सफर, उतना भुगतान का सिद्धांत

इस प्रणाली के तहत जितना सफर, उतना भुगतान का सिद्धांत लागू होगा। वाहन चालकों को पूरे प्लाजा का एकमुश्त शुल्क देने के बजाय सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए केवल उतनी ही दूरी का टोल चुकाना होगा, जितनी दूरी हाईवे पर तय की गई है। नियमों के विरुद्ध बिना फास्टैग या सैटेलाइट ट्रैकर के टोल पार करने पर दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा वाहन को वाहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

बदलाव वाले एक्सप्रेसवे-यहां होगा बदलाव...

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे- दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश (बागपत, शामली) और उत्तराखंड को आपस में जोड़ने वाले इस पूरे निर्माणाधीन 4/6-लेन एक्सप्रेसवे पर शुरुआत से ही बैरियर-मुक्त गेंट्री विन्यास तैयार किया जा रहा।

वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे- यूपी और बिहार के कैमूर, रोहतास तथा औरंगाबाद जिलों से गुजरने वाला यह 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पूरी तरह आधुनिक ओपन-टोलिंग डिजाइन पर बन रहा है।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे- उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार (गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया आदि) के रास्ते पश्चिम बंगाल तक जाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरी तरह गेंट्री आधारित सर्विलांस और टोलिंग सिस्टम से लैस किया जा रहा। यूपी के चार नए लिंक एक्सप्रेसवे- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल लिंक से जोड़ने वाले नेटवर्क, जेवर एयरपोर्ट लिंक, झांसी लिंक और फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के भावी विन्यास में इसी आधुनिक टोल मॉडल को अपनाया जाएगा।

साइबर ठगी के पैसों को ठिकाने लगाने वाला आरोपी दबोचा

नई दिल्ली (एजेंसी)। द्वारका जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने साइबर ठगी की रकम को बैंक खातों के जरिए ठिकाने लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 33 वर्षीय आमिर खान के पास से अलग-अलग बैंकों के नौ डेबिट कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। जांच में दो बैंक खातों में साइबर ठगी के कुल 83,200 रुपये आने के सबूत पुलिस को मिले हैं। पुलिस फिलहाल आरोपियों के साथियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जांच में समाने आया है कि आरोपी कई साइबर ठगी करने वाले गिरोहों को म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 28 अक्टूबर को एंटी नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली थी कि आमिर खान साइबर ठगी से हासिल रकम को निकालने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खाते और डेबिट कार्ड उपलब्ध कराता है। वह खातों में आई रकम में से अपना कमीशन काटकर बाकी पैसे साइबर ठगों को नकद सौंप देता है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर सतीश कुमार की निगरानी में एसआई नवीन कुमार की टीम ने सहयोग विहार स्थित आमिर के घर पर छापा मारकर उसे तीसरी मंजिल के कमरे से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसकी जेब से दो और कमरे की अलमारी से सात डेबिट कार्ड मिले। पूछताछ में उसने कथित तौर पर बताया कि इन कार्डों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम निकालने के लिए किया जाता था। पुलिस ने कार्ड से जुड़े बैंक खातों की जांच समन्वय पोर्टल पर की तो दो खातों में ठगी की रकम मिलने का पता चला। इनमें एक खाते में भुवनेश्वर की महिला से चार अगस्त को 80 हजार रुपये और दूसरे खाते में तमिलनाडु के एक व्यक्ति से 12 अक्टूबर को 3200 रुपये ट्रांसफर हुए थे। पुलिस ने दोनों पीड़ितों से फोन पर संपर्क कर ठगी की पुष्टि भी की। आरोपी के खिलाफ बिंदापुर थाने में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब बरामद अन्य कार्डों और बैंक खातों की जांच कर इस नेटवर्क से जुड़े लोगों का पता लगा रही है।

प्राचीन ज्ञान का नए दृष्टिकोणों के माध्यम से शोध व गहन अध्ययन किया जाना चाहिए: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम-2 का उद्घाटन और मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल (डॉ.) जीडी बख्शी, एसएम, वीएसएम द्वारा लिखित पुस्तक 'वेदास्त्र' जीवन की भाषा - पवित्र ध्वनि से डीएनए-आरएनए' का विमोचन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं को केवल विरासत में मिली धरोहर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि नए दृष्टिकोणों के माध्यम से उनका अन्वेषण, शोध और गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल मौजूदा ज्ञान प्रदान करने वाले संस्थान नहीं हैं, बल्कि ऐसे केंद्र हैं जहां ज्ञान का निरंतर पुनर्निर्माण, संवर्धन और विकास होता है।

इस अवसर पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रो. केके अग्रवाल, प्रो. (डॉ.) रमेश चंद्र गौड़, डीन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मीडिया एंड डिजाइन, मेजर जनरल (डॉ.) जीडी बख्शी, एसएम, वीएसएम, इन्फिनिटी फाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रख्यात लेखक राजीव मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव रश्मि सिंह, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार, तथा सम्पूर्णा फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. शोभा विजेंद्र सहित विश्वविद्यालय के उपाध्यक्षगण, प्रशासनिक अधिकारी, संकाय सदस्य, विद्वान और विद्यार्थी उपस्थित थे।

ऑडिटोरियम-2 के उद्घाटन पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और उसकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मीडिया एंड डिजाइन को बधाई देते हुए गुप्ता ने कहा कि एक ऑडिटोरियम केवल एक भौतिक संरचना नहीं होता, बल्कि वह ऐसा मंच होता है जहां विचारों को अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह नया सभागार बौद्धिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक गतिविधियों, कलात्मक अभिव्यक्ति और अकादमिक चर्चाओं का एक जीवंत केंद्र बनेगा। शैक्षणिक संस्थानों की व्यापक जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को केवल स्थापित ज्ञान के संप्रेषण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके निरंतर विकास और उन्नति में भी योगदान देना चाहिए।

पुस्तक का उल्लेख करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने वेदों को भारत की अमूल्य सभ्यतागत विरासत का अभिन्न अंग बताया, जिसमें दर्शन, भाषा, काव्य, गणित, ब्रह्मांड, प्रकृति और जीवन से जुड़े मौलिक प्रश्नों का समावेश है। उन्होंने कहा कि मेजर जनरल बख्शी की यह कृति वैदिक भाषा और समकालीन वैज्ञानिक अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझने का प्रयास करती है। इसमें डीएनए और आरएनए, गणितीय भाषा, सूचना, जैविक विकास, वैदिक काव्य और साहित्य जैसे विविध विषयों को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया है।

बच्चों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सेफ वॉक टू स्कूल जोन परियोजना शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्वी दिल्ली के 28 स्कूलों के आसपास बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 'सेफ वॉक टू स्कूल जोन' पायलट परियोजना शुरू की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद हर्ष मल्होत्रा ने सोमवार को वसुंधरा एन्क्लेव स्थित सोमरविले स्कूल से इसका शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसमें पैदल चलने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतर फुटपाथ, सुरक्षित पैदल पार पथ, स्पष्ट सड़क संकेतक, रिफ्लेक्टिव रोड मार्किंग और यातायात को नियंत्रित करने के उपायों पर जोर रहेगा। साथ ही, स्कूलों के आसपास वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस दौरान ट्रांस यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन के चेयरमैन यशपाल कैंतुरा उपस्थित रहे।

भाजपा ने पदयात्रा निकाल सिख दंगे में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, एजेंसी।

1984 के सिख दंगे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर फिर निशाना साधा है। सोमवार को दिल्ली भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सिख संगत और दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब से गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब तक गुरुबाणी का जाप करते हुए श्रद्धांजलि पदयात्रा निकाली। वहां पहुंचने के बाद सिख दंगे में जान गंवाने वालों की स्मृति में मोमबत्तियां जलाई गईं।

सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सिखों के खिलाफ हुए नरसंहार में लोगों को संगठित तरीके से निशाना बनाया गया था। आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के समर्थित लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि कांग्रेस ने कभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फिर से सिख समाज के जख्मों को न कुरेदें और देश में अराजकता न फैलाएं।

सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहकर नरसंहार को जायज ठहराने की कोशिश की थी कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राहुल गांधी ने एक नवंबर को रैली निकालने का दिन चुन कर उसी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और नौकरियां देने के साथ दोषियों को सजा दिलाने का काम किया, जिसका उदाहरण सज्जन कुमार को मिली सजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की रैली में किसी भी नेता ने 1984 के सिख दंगे पर एक शब्द नहीं बोला। इस पदयात्रा में पीड़ित परिवारों के सदस्य सरदार करतार सिंह, प्रीति सिंह कौर, जसवीर कौर, भागी कौर, परमजीत कौर, मनप्रीत कौर के साथ भाजपा नेता राजीव बब्बर, मोहनलाल गिहारा, योगिता सिंह, कैलाश जैन आदि शामिल हुए।



संक्षिप्त समाचार

बैनामा लेखक की पड़ोसी वकील को फंसाने की साजिश का खुलासा, तीन गिरफ्तार

अनप्लग इंडिया

ग्रेटर नोएडा। पुलिस ने बैनामा लेखक पर हुई फायरिंग मामले का सोमवार को पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साजिशकर्ता, उसका भाई और एक साथी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक बैनामा लेखक हरेंद्र नागर ने अपने हिस्ट्रीशीटर भाई के साथ मिलकर अपने पड़ोसी विकल विकास सैन को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग कराई थी।

ग्रेटर नोएडा के डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि दादरी कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार दो युवकों ने 25 अक्तूबर को बैनामा लेखक हरेंद्र नागर के ऊपर फायरिंग की थी। बैनामा लेखक ने इस मामले में अपने पड़ोसी वकील विकास सेन को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। पुलिस की जांच में सामने आया की घटना के समय आरोपी विकास अपने घर पर था।

पुलिस की जांच में सामने आया कि वादी हरेंद्र नागर ने अपने हिस्ट्रीशीटर भाई सत्ते, भतीजे प्रतीक उर्फ कलुआ, साले अतुल भाटी और बेटे अभिषेक नागर समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। इसके तहत अतुल भाटी और कलुआ उर्फ प्रतीक को घर बुलाकर कैमरे के सामने खुद पर फायरिंग कराई। इसके बाद पड़ोसी विकास सैन के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मनगढ़ंत घटना का खुलासा कर सोमवार को बिसाहड़ा अंडरपास से तीन वांछित आरोपी प्रतीक उर्फ कलुआ, अतुल भाटी और अभिषेक नागर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, एक बाइक और सीसीटीवी की डीवीआर बरामद की। पुलिस साजिशकर्ता वादी हरेंद्र, उसके भाई सत्ते और आकाश चपराना की तलाश में जुटी है।

डीसीपी ने बताया कि वादी हरेंद्र और उसका भाई सतेंद्र उर्फ सत्ते को दादरी में वर्ष 2007 में हुई एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। दोनों भाई पैरोल पर जेल से छूटकर बाहर आए हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर पड़ोसी को फंसाने के लिए साजिश रची। डीसीपी के मुताबिक बताया जा रहा है कि खुद के ऊपर फायरिंग करने का मकसद असलाह का लाइसेंस बनवाना और सुरक्षा गनर लेना था। हालांकि, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी हरेंद्र और उसके भाई सत्ते के पकड़े जाने के बाद घटना का सही मकसद पता चल सकेगा।

पुलिस की शुरुआती जांच में आरोपी पड़ोसी विकास के बेगुनाह साबित होने पर इस मामले की गहनता से जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। इसके बाद पुलिस ने 10 किलोमीटर के दायरे में करीब 100 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज देखी। इसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची और इस घटना का खुलासा किया। डीसीपी ने बताया कि घटनाक्रम का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये को इनाम देने की घोषणा की गई है।

फोनरवा की मांग पशुओं के लिए बने आधुनिक शवदाह गृह

अनप्लग इंडिया

नोएडा। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन्स (फोनरवा) ने मृत आवारा एवं पालतू पशुओं के पर्यावरण-अनुकूल अंतिम संस्कार के लिए आधुनिक पशु शवदाह केंद्र स्थापित करने की मांग की है। फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा एवं महासचिव के.के. जैन ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखकर यह मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि नोएडा में मृत पशुओं के शवों का समयबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना आवश्यक है। कई बार उचित व्यवस्था के अभाव में मृत पशुओं के शव सार्वजनिक स्थलों अथवा आवासीय क्षेत्रों में पड़े रहने से दुर्गंध, गंदगी, संक्रमण की आशंका एवं पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनकी मांग है कि पर्यावरण-अनुकूल पशु शवदाह केंद्र स्थापित किया जाए। इसके लिए उपयुक्त स्थान का चयन, मशीन की तकनीकी क्षमता एवं प्रदूषण नियंत्रण मानकों का परीक्षण तथा आवश्यक बजट एवं परियोजना प्रस्ताव तैयार कराया जाए।

कार का शीशा तोड़कर नकदी और लैपटॉप चुराए- कासना कस्बे में बदमाशों ने निजी अस्पताल के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर दो लैपटॉप और 55 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। पीड़ित अस्पताल में भर्ती अपने किसी परिचित को देखने गए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कासना कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एल्डिको मिडोज सोसाइटी निवासी नरेंद्र सिंह के परिचित कासना कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वह 31 अक्तूबर को उन्हें देखने अस्पताल गए थे। उन्होंने अपनी कार अस्पताल के बाहर सड़क किनारे खड़ी की थी। वह अपने परिचित से मिलकर बाहर आए तो कार का शीशा टूटा मिला। कार में रखा बैग गायब था, जिसमें 55 हजार रुपये और दो लैपटॉप थे। उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी जा रही है। चोरों का पता लगाकर सामान बरामद किया जाएगा।

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की रैली से विपक्ष होगा मजबूत : राकेश टिकैत

अनप्लग इंडिया

गाजियाबाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में आयोजित इंडिया ब्लॉक की महारैली, जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों, किसानों की चुनावी रणनीति और राजधानी में प्रदूषण को लेकर लागू किए जा रहे नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। टिकैत ने कहा कि दिल्ली में आयोजित विपक्ष की रैली से विपक्षी दलों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि रैली में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे।

राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित रैली का उल्लेख करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वर्ष 2020 के दिल्ली किसान आंदोलन के बाद विपक्ष की यह पहली बड़ी रैली थी। उन्होंने कहा कि अब तक किसान अपने स्तर पर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने पहली बार इस तरह का बड़ा आयोजन किया है। विपक्ष को प्रदेश स्तर पर भी इसी तरह बड़ी रैलियां आयोजित करनी चाहिए, जिससे उसकी एकजुटता और ताकत बढ़ सके।

जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों और वर्ष 2027 तथा 2029 के चुनावों में युवाओं की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर टिकैत ने कहा कि युवा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, उनका आंदोलन अच्छा है। उन्होंने कहा कि युवा और बच्चे आगे आ रहे हैं तथा देश का युवा वर्ग भी उनके साथ जुड़ रहा है।

चुनाव में किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेगी भाकियू

किसानों की चुनावी रणनीति को लेकर राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि भारतीय किसान यूनियन किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में समर्थन नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सभी लोगों को एकजुट होकर साथ रहना चाहिए, लेकिन चुनाव में किसे मतदान करना है, यह प्रत्येक व्यक्ति का अपना निर्णय है। आंदोलन में शामिल होने वाले लोग सत्ता पक्ष को भी मतदान करते हैं। इसलिए आंदोलन और चुनाव को अलग-अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए।

10 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध को बताया गलत

दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर 10 साल पुरानी गाड़ियों के प्रवेश पर लगाए जा रहे प्रतिबंध को लेकर टिकैत ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आधार उनकी उम्र नहीं, बल्कि उनकी फिटनेस होनी चाहिए। वाहनों की स्थिति और उनके वास्तविक इस्तेमाल को ध्यान में रखकर नियम बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक वाहनों और घरों में खड़ी रहने वाली निजी गाड़ियों के इस्तेमाल में काफी अंतर होता है।

ग्राउंड से ओलंपिक पोडियम तक: नोएडा में पैरा-एथलीटों का सम्मान, मुकेश शर्मा ने साझा किया खेलों के विकास का विजन

अनप्लग इंडिया

नोएडा। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और दिव्यांग खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान देने की दिशा में नोएडा में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। गौरी शिक्षा फाउंडेशन और प्रोमेथियस स्पोर्ट्स अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार, 1 नवंबर को प्रोमेथियस स्कूल में 'नोएडा स्पोर्ट्स टैलेंट हंट - एडिशन 2' का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। इस दौरान एशियन पैरा गेम्स 2026 में देश का गौरव बढ़ाने वाले भारतीय पैरा-एथलीटों और पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया।

समारोह में खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। आयोजकों की ओर से स्वर्ण पदक विजेताओं को एक लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को 75 हजार रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई।

दो स्वर्ण जीतने वाली सिमरन शर्मा का भी सम्मान

समारोह में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार और 100 मीटर एवं 200 मीटर दौड़ में दोहरे स्वर्ण पदक हासिल करने वाली सिमरन शर्मा की उपलब्धियों की विशेष सराहना की गई।



इसके अलावा 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाली प्रीति पाल, पैरा बैडमिंटन युगल में कांस्य पदक विजेता सूर्यकांत यादव, पैरा तीरंदाजी में रजत पदक विजेता स्वाति चौधरी, ऊंची कूद में रजत पदक विजेता वरुण सिंह भाटी, भाला फेंक में रजत पदक विजेता अजीत सिंह और पावरलिफ्टिंग में रजत पदक हासिल करने वाले अशोक मलिक को सम्मानित किया गया।

वहीं, पैरा तीरंदाजी युगल में रजत पदक विजेता भावना चौधरी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार सहित अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की गई।

जमीनी स्तर से ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का लक्ष्य

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोमेथियस स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष एवं गौरी शिक्षा फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी मुकेश शर्मा ने कहा कि भारत में खेलों के विकास के लिए मजबूत आधारभूत ढांचे और प्रतिभाओं की शुरुआती स्तर पर पहचान करना बेहद जरूरी है।

उन्होंने बताया कि प्रोमेथियस स्पोर्ट्स अकादमी में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, शूटिंग और जिम्नास्टिक जैसी खेल सुविधाएं विकसित की गई हैं। संस्थान का लक्ष्य बच्चों को शुरुआती स्तर से प्रशिक्षित कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है, ताकि वे भविष्य में ओलंपिक और पैरालंपिक पोडियम तक पहुंच सकें।

मुकेश शर्मा ने खेल संस्कृति को मजबूत बनाने में माता-पिता की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक खेल से जरूर जुड़ना चाहिए। इससे बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है।

उन्होंने देश में खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए काम कर रहे 'ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट' के प्रयासों की भी सराहना की।

स्थानीय प्रतिभाओं को मिलेगी छात्रवृत्ति और बेहतर प्रशिक्षण

गौरी शिक्षा फाउंडेशन और प्रोमेथियस स्पोर्ट्स अकादमी की इस पहल का उद्देश्य केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना भी है।

नोएडा स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के माध्यम से उभरते खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद चयनित प्रतिभाओं को छात्रवृत्ति, उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल मंच उपलब्ध कराने की योजना है।

आयोजकों का मानना है कि यदि खिलाड़ियों को शुरुआती दौर से ही सही मार्गदर्शन, आधुनिक सुविधाएं और आर्थिक सहयोग मिले तो भारत ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है।

खेलों में प्रतिभा के साथ अवसर और संसाधन भी जरूरी

नोएडा में आयोजित यह समारोह खिलाड़ियों के सम्मान के साथ-साथ खेलों के लिए बेहतर अवसर तैयार करने की जरूरत को भी सामने लाता है। पैरा-एथलीटों की उपलब्धियां यह संदेश देती हैं कि प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के सामने चुनौतियां बाधा नहीं बन सकतीं। जरूरत है तो सिर्फ सही मंच, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की।

नोएडा के लोगों को मिलेगा साफ पानी

45 करोड़ से बनेंगे 2 नए रैनीवेल, रोजाना 34 MLD वाटर की होगी सप्लाई

अनप्लग इंडिया

नोएडा। नोएडा में पानी की सप्लाई बेहतर करने के लिए प्राधिकरण दो नए रैनीवेल बनाएगा। ये सेक्टर-132 और 135 में यमुना किनारे बनाए जाएंगे। दोनों की क्षमता 17-17 एमएलडी होगी। इनसे रोजाना 34 एमएलडी पानी की सप्लाई हो सकेगी। परियोजना पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन रैनीवेल से लोगों को 300 से 400 टीडीएस वाला पानी देने की योजना है। गंग नहर की सफाई या तकनीकी खराबी के कारण गंगाजल की सप्लाई बंद होने पर इनसे शहर की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी।

नोएडा में रोजाना 450 एमएलडी से ज्यादा पानी की मांग

नोएडा में रोजाना 450 एमएलडी से ज्यादा पानी की जरूरत है। शहर को गंगाजल से करीब 240 एमएलडी पानी मिलता है। इसके अलावा नलकूपों से 110 एमएलडी और रैनीवेल से करीब 100 एमएलडी पानी की सप्लाई होती है। गंगाजल की सप्लाई गाजियाबाद के प्रताप विहार और सिद्धार्थ विहार प्लांट से की जाती है।

अभी 8 रैनीवेल चल रहे, 3 और जल्द शुरू होंगे

जीएम जल आरपी सिंह ने बताया कि नोएडा में अभी 8 रैनीवेल से रोजाना करीब 100 एमएलडी पानी मिल रहा है। तीन अन्य रैनीवेल भी जल्द शुरू किए जाएंगे। सेक्टर-132 और 135 में दो नए रैनीवेल बनाए जाएंगे। सभी के शुरू होने के बाद रैनीवेल से करीब 160 एमएलडी पानी की सप्लाई हो सकेगी।

गंग नहर की सफाई के दौरान नहीं होगी परेशानी

गंग नहर की सफाई या तकनीकी खराबी के कारण गंगाजल की सप्लाई बंद होने पर शहर में पानी की कमी हो जाती है। नए रैनीवेल शुरू होने से इस कमी को पूरा



करने में मदद मिलेगी। इससे लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

फरीदाबाद मॉडल पर काम कर रहा प्राधिकरण

अधिकारियों के मुताबिक, फरीदाबाद में करीब 32 रैनीवेल चल रहे हैं। वहां पानी की सप्लाई में इनका बड़ा योगदान है। इसी मॉडल पर नोएडा में भी रैनीवेल की संख्या बढ़ाई जा रही है। यमुना किनारे नए रैनीवेल बनाकर पानी की उपलब्धता बढ़ाने की योजना है।

यूपी में दिवाली और छठ पर इन जिलों के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें

अनप्लग इंडिया

गाजियाबाद। गाजियाबाद में दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रोडवेज बसों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। यूपी रोडवेज ने इसके लिए 300 बसों के अतिरिक्त फेरे लगवाने की तैयारी की है। इससे यात्रियों को मेरठ, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़ समेत अन्य शहरों को जाने के लिए समय से बस मिल सकेंगी।

दीपावली पर अपने घर जाने के लिए कौशांबी डिपो से बड़ी संख्या में यात्री रवाना होते हैं। त्योहार के समय यात्रियों के बस के लिए अधिक समय इंतजार न करना पड़े और बसों की कमी से न जूझना पड़े, इसके लिए परिवहन निगम विभिन्न रूट पर बसों के फेरे बढ़ाएगा।

गाजियाबाद रीजन के 7 डिपो से चलाई जाएंगी 300 और बसें

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन चौधरी ने बताया कि परिवहन निगम ने 5 नवंबर से 300 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की है। गाजियाबाद रीजन के सात डिपो से इन बसों का संचालन किया जाएगा। बसें आनंद विहार और कौशांबी बस अड्डे से यात्रियों की भीड़ के अनुसार रवाना होंगी।

यूपी के इन रूटों पर चलेंगी बसें

दिल्ली से लखनऊ, बरेली, हरदोई, आजमगढ़, सोनौली, बदायूं, मैनपुरी, कानपुर और एटा-अलीगढ़ मार्ग पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इनमें 243 साधारण, 55 जनरथ और एसी शताब्दी व दो हाई एंड बसें शामिल हैं। सबसे अधिक 70 बसें बदायूं मार्ग पर लगाई जाएंगी। बसों के संचालन और निगरानी के लिए 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा लाल कुआं, मोहन नगर चौराहा और सेक्टर 62 पर बसों को रोककर चलाने के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी।

अस्थायी सहायता केंद्र बनाया जाएगा

यात्रियों की सुविधा के लिए कौशांबी बस डिपो पर अस्थायी सहायता केंद्र बनाया जाएगा। यहां तीन शिफ्ट में छह कर्मचारियों की तैनाती होगी। कर्मचारी यात्रियों को



बसों के रूट, समय-सारिणी, उपलब्धता और गंतव्य से संबंधित जानकारी देंगे। त्योहार पर बस अड्डे पहुंचने वाले यात्रियों को बस खोजने और सही रूट की जानकारी लेने में परेशानी नहीं होगी। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को बसों से संबंधित जानकारी देने के साथ जरूरी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

त्योहार पर बसों में गूंजेंगे भजन और लोकगीत

दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों के सफर को खुशनुमा बनाने के लिए परिवहन निगम की बसों में भजन और लोकगीत बजाए जाएंगे। बसों में धार्मिक और पारंपरिक गीतों के माध्यम से यात्रियों को त्योहारों का एहसास कराया जाएगा। खासतौर पर दिवाली और छठ से जुड़े लोकगीतों को प्राथमिकता दी जाएगी। लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

जेवर एयरपोर्ट पर दो महीने में 27 फीसदी घटे यात्री

देखें जून से सितंबर तक के आंकड़े

अनप्लग इंडिया

ग्रेटर नोएडा। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। महज दो महीने में यात्रियों की संख्या में 20,703 की कमी आई। जुलाई की तुलना में सितंबर में यात्रियों की संख्या करीब 27 फीसदी घट गई।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का संचालन 15 जून 2026 को शुरू हुआ था। जून और जुलाई में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में शुरुआती तेजी के बाद लगातार गिरावट आ रही है। जुलाई में एयरपोर्ट से 76,593 यात्रियों ने सफर किया था। इसके बाद अगस्त में यात्रियों की संख्या 58,520 रही। सितंबर में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अगस्त के बीच यात्रियों की संख्या 18073 यानी 24 प्रतिशत कम रही। अगस्त से सितंबर के बीच 2630 यात्री और



कम हुए। यह गिरावट 4.49 फीसदी रही। इसके साथ ही 15 जून से 30 सितंबर तक एयरपोर्ट से कुल 2,11,525 यात्री सफर कर चुके हैं।

उम्मीद है कि अक्टूबर में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। अक्टूबर में एयरपोर्ट से कोलकाता, चंडीगढ़ और उदयपुर के लिए भी उड़ानें शुरू हुई हैं। तीन नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू होने से यात्रियों की संख्या में वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, अब भी प्रतिदिन 14 से 15 शहरों के लिए ही उड़ानें रहती हैं।

72 प्रतिशत सीटें खाली रहीं

सितंबर के यात्री आंकड़ों और रोजाना 32 से 36 विमानों की आवाजाही के आधार पर रनवे पर लैंडिंग और टेकऑफ करने वाले प्रत्येक विमान में 68 से 72 प्रतिशत तक सीटें खाली रहीं। एयरपोर्ट से इंडिगो ओर अकासा के विमान हवाई सेवाएं दे रहे हैं। इन विमानों में 180 से 186 सीटें होती हैं। ऐसे में प्रत्येक विमान में 52 से 58 यात्रियों ने सफर किया।

बेंगलुरु -लखनऊ समेत चार उड़ानों में देरी

एयरपोर्ट से रविवार दोपहर 3: 20 बजे लखनऊ के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट शाम 4:17 बजे रवाना हो सकी। दोपहर 2:40 बजे बेंगलुरु के लिए जाने वाली फ्लाइट तीस मिनट की देरी से रवाना हुई। धर्मशाला के लिए सुबह 9:35 बजे जाने वाली फ्लाइट 30 मिनट से ज्यादा की देरी से उड़ान भर सकी। बरेली की फ्लाइट 20 मिनट की देरी से रवाना हुई।

बता दें कि, जेवर एयरपोर्ट ने जिले और प्रदेश को एक नई पहचान दी है। वर्मान में यहां से देश के कई शहरों के लिए घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं और नए साल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू किए जाने की उम्मीद है।

एटीएस हैप्पी ट्रेल्स के सामने अवैध ठेलों से जाम लग रहा

अनप्लग इंडिया

ग्रेटर नोएडा। एटीएस हैप्पी ट्रेल्स सोसाइटी के सामने मुख्य सड़क पर अवैध फूड स्टॉल, ठेले और अस्थायी दुकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनके चलते सड़क पर दिन में तीन से चार बार जाम लग रहा है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो जाती है। वहीं, दुकानों पर आने वाले कुछ लोग सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर उनमें बैठकर शराब का सेवन भी करते हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है।

निवासी प्रतीश का कहना है कि सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगने के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। दुकानों पर आने वाले लोगों की गाड़ियां भी सड़क पर खड़ी रहती हैं, जिससे रास्ता और संकरा हो जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने की घटनाओं से असुरक्षा का माहौल बन रहा है। लोगों को आशंका है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये अस्थायी दुकानें धीरे-धीरे स्थायी अतिक्रमण का रूप ले लेंगी और भविष्य में इन्हें हटाना मुश्किल होगा। इसकी शिकायत पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी।

निवासियों ने संबंधित अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका

निवासी प्रतीश का कहना है कि सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगने के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। दुकानों पर आने वाले लोगों की गाड़ियां भी सड़क पर खड़ी रहती हैं,

कहना है कि मौके पर विभागीय टीम भेजकर अवैध दुकानों और ठेलों को हटाया जाए। साथ ही सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर रोक लगाने और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि यह मामला हजारों निवासियों की सुरक्षा और रोजाना के आवागमन से जुड़ा है, इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।

जन्मदिन से पहले बृजभूषण को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट, बेटी शालिनी ने दिया लाखों का हेलीपैड

अनप्लग इंडिया

गोंडा। यूपी के कद्दावर नेता और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन से पहले बड़ा तोहफा मिला है। ये तोहफा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी शालिनी सिंह ने उन्हें सौंपा हैं। नोएडा में रह रहीं शालिनी ने अपने को पिता जन्मदिन के तोहफे के रूप में एक हेलीपैड गिफ्ट किया है। पिता को हेलीपैड गिफ्ट करने की खुशी शालिनी ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी साझा की है। जन्मदिन से पहले इतने बड़े गिफ्ट को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। बेटी से गिफ्ट मिलने के बाद पिता बृजभूषण सिंह भावुक हो गए। उन्होंने गिफ्ट को स्वीकार करते हुए हेलीपैड का तुरंत विधिवत रूप से उद्घाटन भी कर डाला।

आठ जनवरी को बृजभूषण शरण का जन्मदिन है। पिता के जन्मदिन को यादगार



बनाने के लिए बेटी शालिनी ने अनूठी पहल की और हेलीपैड देने का सरप्राइज प्लान किया। हेलीपैड की कीमत कीतनी है इसको लेकर कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स इसकी कीमत लाखों में बता रहे हैं। शालिनी सिंह की ससुराल बिहार में है। फिलहाल वह नोएडा में रह रही हैं। शालिनी नोएडा सिटिजन फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा भाजपा की सक्रिय कार्यकत्री भी हैं। शालिनी अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान का हर संभव प्रयासरत रहती हैं।

बृजभूषण के पास हैं तीन हेलीकॉप्टर

यूपी के बाहुबली नेता और गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बेहद ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। उनके बेड़े में एक से एक लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है। इसके बाद बृजभूषण सिंह को घुड़सवारी का भी शौक है। उनके बाड़े में कई महंगे घोड़े शामिल हैं। मौजूदा समय में पूर्व सांसद के पास तीन हेलीकॉप्टर भी हैं। इनमें से एक सफेद, एक काला और एक भगवा रंग का हेलीकॉप्टर है। काले रंग का हेलीकॉप्टर नोएडा के नए हेलीपैड पर हमेशा खड़ा रहेगा। इससे उनकी बेटी शालिनी को भी ससुराल आने-जाने में सहूलियत हो जाएगी। भगवा और सफेद रंग के हेलीकॉप्टर बृजभूषण के आने-जाने के लिए गोंडा में रहेंगे। इन हेलीकॉप्टरों से पूर्व सांसद दूर-दराज के क्षेत्रों में आने-जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे।

एक साल पहले ही खरीदा था भगवा रंग का हेलीकॉप्टर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेड़े में अभी तीन हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। पहले उनके पास काला और सफेद रंग के दो हेलीकॉप्टर थे। पिछले साल उन्होंने एक भगवा रंग का हेलीकॉप्टर खरीदा था। आर-66 मॉडल वाले इस हेलीकॉप्टर की कीमत करीब सात से आठ करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है। इन हेलीकॉप्टरों से बृजभूषण शरण सिंह दूरा-दराज के क्षेत्रों और दूसरे प्रदेशों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाते रहते हैं।

संपादकीय

किसानों को ग्रीन अमोनिया से सस्ती खाद की उम्मीद

भारतीय कृषि लंबे समय से बढ़ती लागत और घटती आमदनी की चुनौती व पुरानी रुढ़िवादी तकनीक से जूझ रही है। डीजल, बिजली, बीज, कीटनाशक और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि ने किसानों के सामने आर्थिक संकट को और गहरा किया है। खेती की लागत में उर्वरकों की हिस्सेदारी भी काफी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से यूरिया की उपलब्धता और उसकी कीमत किसानों के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशना एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा सकती है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले समय में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है। हालांकि, इस पहल की वास्तविक सफलता केवल तकनीकी प्रयोग तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका लाभ खेतों में काम करने वाले किसानों तक पहुंचना भी जरूरी है।



किसानों के लिए खुश खबरी आई है कि सरकार छह राज्यों में लगभग 10 हजार एकड़ भूमि पर ग्रीन अमोनिया के उपयोग का परीक्षण कर रही है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि पारंपरिक नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल कितना प्रभावी और किफायती हो सकता है। ग्रीन अमोनिया का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से तैयार हाइड्रोजन के माध्यम से किया जाता है। इसके विपरीत परंपरागत अमोनिया उत्पादन में मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की अधिक खपत के साथ कार्बन उत्सर्जन भी होता है। इसलिए ग्रीन अमोनिया को न केवल कृषि की लागत कम करने, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक संभावनाशील विकल्प माना जा रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी के अनुसार, अमोनिया को सीधे मिट्टी में डालने से उर्वरक की लागत मौजूदा स्तर से लगभग एक-तिहाई तक घट सकती है। यदि यह अनुमान व्यावहारिक रूप से सही साबित होता है तो खाद उत्पादन और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल भी है कि उत्पादन लागत में संभावित कमी का लाभ किसानों को किस रूप में मिलेगा? क्या इससे यूरिया की खुदरा कीमत घटेगी, या सरकार की सब्सिडी का बोझ कम होगा? इन सवालों का जवाब परीक्षण के परिणाम और सरकार की नीतिगत व्यवस्था से ही मिलेगा।

दरअसल, भारत में यूरिया केवल एक औद्योगिक उत्पाद नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। देश में बड़ी संख्या में किसान नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया पर निर्भर हैं। सरकार किसानों को सस्ती दरों पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए भारी सब्सिडी देती है। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर उर्वरक क्षेत्र पर पड़ता है। भारत को उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और गैस की उपलब्धता के मामले में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

तटीय क्षेत्रों पर मंडराता मुरासु चक्रवात का संकट



महेन्द्र तिवारी
साहित्यकार एवं लेखक
पूर्व वायुसैनिक, नई दिल्ली

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मुरासु ने दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है। मौसम की बदलती परिस्थितियों के बीच तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। संभावित खतरे को देखते हुए 2 नवंबर को चेन्नई के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन का यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। चक्रवाती तूफान की आहट ने एक बार फिर यह प्रश्न सामने ला दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए कितनी सतर्कता और तैयारी आवश्यक है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मुरासु चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी और उससे लगे पश्चिम-मध्य क्षेत्र में सक्रिय है। 1 नवंबर की शाम यह चेन्नई से लगभग 420 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित था और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। मौसम विभाग ने इसके अधिक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई थी। पूर्वानुमान के अनुसार, इसके आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर नेल्लोर और नरसापुर के बीच, ओंगोल के आसपास, 2 नवंबर की देर रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच पहुँचने की संभावना है। उस समय हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है और झोंकों की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की आशंका है।

चक्रवाती तूफान का केंद्र किसी स्थान से दूर होने का अर्थ यह नहीं है कि वहाँ खतरा नहीं है। तूफान के चारों ओर फैले बादल, वर्षा की पट्टियाँ और तेज हवाएँ दूरवर्ती क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती हैं। चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर और नीलगिरि सहित तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इन परिस्थितियों में जलभराव, यातायात बाधित होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

चेन्नई में विद्यालयों को बंद रखने का निर्णय इसी संभावित खतरे को ध्यान में रखकर लिया गया है। विद्यालय जाने वाले बच्चों को प्रतिदिन घर से निकलकर परिवहन के विभिन्न साधनों से अपने शिक्षण संस्थानों तक पहुँचना पड़ता है। भारी वर्षा के दौरान सड़कों पर पानी भर जाने, नालों के उफनने और यातायात की गति धीमी होने से उनकी यात्रा जोखिमपूर्ण हो सकती है। कई बार सामान्य दिखाई देने वाली सड़क पर भी पानी की गहराई का अनुमान लगाना कठिन होता है। खुले नालों, गड्ढों और जलमग्न विद्युत उपकरणों के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में अवकाश घोषित करना केवल शैक्षणिक गतिविधियाँ रोकना नहीं, बल्कि बच्चों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक आवश्यक उपाय है। प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रशासन की जिम्मेदारी केवल चेतावनी जारी करने तक सीमित नहीं रहती। मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखना, नागरिकों तक समय पर सूचना पहुँचाना, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और आवश्यकतानुसार राहत व्यवस्था तैयार रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला अधिकारियों को सतर्क रहने तथा निर्धारित आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय रखने, आवश्यक तैयारियाँ करने और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र तक पहुँचाने को कहा गया है।

चेन्नई जैसे बड़े नगरों के सामने चक्रवाती तूफान के समय कई तरह की चुनौतियाँ एक साथ खड़ी हो जाती हैं। यहाँ



बड़ी आबादी रहती है, यातायात का दबाव अधिक है और अनेक क्षेत्र वर्षा के दौरान जलभराव से प्रभावित होते हैं। यदि कुछ घंटों में बहुत अधिक पानी बरसता है, तो सड़कों पर आवागमन बाधित हो सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दुकानदारों, छोटे कारोबारियों, दैनिक मजदूरी करने वालों और सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। इसलिए चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारी में केवल तात्कालिक राहत नहीं, बल्कि नगर की दीर्घकालिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए।

वर्षा का पानी प्राकृतिक जलमार्गों से निकलकर नदियों, झीलों और समुद्र तक पहुँचता है। जब इन जलमार्गों पर अतिक्रमण होता है, नालों में कचरा जमा रहता है या जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती, तब सामान्य से अधिक वर्षा भी गंभीर समस्या बन सकती है। अनियोजित निर्माण और प्राकृतिक जलस्रोतों की उपेक्षा नगरों की संवेदनशीलता बढ़ाती है। चेन्नई सहित अनेक तटीय नगरों के लिए यह आवश्यक है कि वर्षा जल निकासी की व्यवस्था नियमित रूप से जाँची जाए, नालों की सफाई समय पर हो और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में पहले से तैयारी रखी जाए।

इस घटना का प्रभाव केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं माना जा सकता। मुरासु के आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने के कारण वहाँ भी प्रशासन सतर्क है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, मछुआरों और समुद्र पर निर्भर समुदायों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होती हैं। समुद्र में ऊँची लहरें उठने और तेज हवाएँ चलने के दौरान मछली पकड़ने वाली नौकाओं का संचालन जोखिमपूर्ण हो सकता है। मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना और समुद्र में जाने से बचना ऐसे समय में जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

चक्रवाती तूफान के समय नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए। बिना पुष्टि वाली खबरों और भ्रामक संदेशों को आगे भेजने से बचना चाहिए। घरों में पीने का पानी, आवश्यक खाद्य सामग्री, प्राथमिक उपचार की वस्तुएँ, टॉर्च और आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध रखना उपयोगी हो सकता है। तेज हवाओं के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहना चाहिए। जलभराव वाले रास्तों से गुजरने या बहते पानी में वाहन चलाने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। यदि प्रशासन किसी क्षेत्र को खाली करने का निर्देश देता है, तो उसका पालन करना चाहिए।

विद्यालयों में अवकाश की घोषणा के साथ अभिभावकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि खराब मौसम में घर से बाहर निकलना क्यों जोखिमपूर्ण हो सकता है। अवकाश के दौरान उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना, बिजली चमकने और तेज हवाएँ चलने पर सावधानी बरतना तथा प्रशासन की नई सूचनाओं पर नजर रखना जरूरी है। विद्यालय प्रबंधन को भी विद्यार्थियों और अभिभावकों तक सही सूचना पहुँचाने की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

चक्रवाती तूफान प्रकृति की एक शक्तिशाली मौसमी घटना है, लेकिन उससे होने वाली क्षति को समय पर तैयारी, वैज्ञानिक पूर्वानुमान और सामूहिक सतर्कता से काफी हद तक कम किया जा सकता है। मौसम विज्ञान की प्रगति ने अब तूफानों की दिशा, गति और संभावित प्रभावों का अनुमान पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित ढंग से लगाने में सहायता की है। आवश्यकता इस बात की है कि इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें व्यवहार में उतारा जाए।

चेन्नई में विद्यालयों का बंद रहना एक अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन इसके पीछे बच्चों की सुरक्षा का बड़ा उद्देश्य है। तूफान की तीव्रता और वर्षा की वास्तविक स्थिति के अनुसार आगे के निर्णय लिए जाएँगे। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक घबराएँ नहीं, पर लापरवाही भी न बरतें। प्रशासन, मौसम विभाग और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय ही इस चुनौती का सामना करने का प्रभावी मार्ग है। मुरासु की आहट हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन समझदारी, तैयारी और एकजुटता से जीवन और संपत्ति की रक्षा अवश्य की जा सकती है।

सूरत में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल आखिर कब टूटेगा

-कांतिलाल मांडोत-

चिकित्सा का पेशा केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि मानव जीवन बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बनने के लिए वर्षों की पढ़ाई, प्रशिक्षण और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत में ऐसे लोगों की संख्या लगातार सामने आ रही है, जिनके पास मान्य मेडिकल डिग्री नहीं है, लेकिन वे बाकायदा डॉक्टर बनकर क्लीनिक चला रहे हैं। मरीजों को दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और बीमारियों का उपचार करते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की लगातार छापेमारी ने इस अवैध कारोबार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे उजागर कर दिया है।

अक्टूबर महीने में सूरत में हुई कार्रवाइयों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 14 अक्टूबर को पांडेसरा में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने 16 कथित झोलाछाप डॉक्टरों को पकड़ा था। उनके कब्जे से 1.82 लाख रुपये की दवाइयां और चिकित्सा उपकरण जब्त किए गए थे। इससे पहले 16 सितंबर को पांडेसरा में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके यहां से 98,825 रुपये का सामान जब्त हुआ था। वहीं 11 सितंबर को पांडेसरा में दो अन्य कथित फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा गया था। इन दोनों के क्लीनिक से लगभग 47 हजार रुपये का सामान जब्त किए जाने की खबर सामने आई थी। इस प्रकार सितंबर और अक्टूबर में सामने आई इन तीन कार्रवाइयों में ही 26 लोगों को पकड़े जाने की जानकारी सार्वजनिक हुई थी।

इसके बाद 29 अक्टूबर को डिंडोली में एसओजी और जिला स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नौ कथित झोलाछाप डॉक्टरों को पकड़ा। इनके पास से 95,138 रुपये की दवाइयां, इंजेक्शन, सिरप और मेडिकल उपकरण जब्त किए गए। पुलिस ने कार्रवाई से पहले डमी मरीज भेजकर क्लीनिकों की जांच भी करवाई थी। जांच में सामने आया कि कुछ लोग दसवीं और बारहवीं पास थे, तो कुछ के पास सामान्य स्नातक की डिग्री थी। कुछ लोग पहले अस्पतालों में कंपाउंडर या सहायक के रूप में काम कर चुके थे।

30 अक्टूबर को सचिन जीआईडीसी में चार क्लीनिकों पर छापेमारी हुई। रामबहादुर वर्मा, आशीष मौर्य, नरोत्तम बैरागी और महेंद्र पंवार को पकड़ा गया। इन चारों के पास एलोपैथी चिकित्सा करने की मान्य डिग्री नहीं थी। पुलिस ने 47,455 रुपये का सामान जब्त किया। इसी दौरान सचिन क्षेत्र में तीन अन्य लोगों अरुणक्रांति विश्वास, चंद्रेश कुमार प्रजापति और सुशांत बिश्वास के खिलाफ भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई। उनके क्लीनिकों से 71,220 रुपये का सामान जब्त किया गया। इस प्रकार सितंबर से अक्टूबर तक उपलब्ध अलग-अलग समाचार रिपोर्टों में कुल 33 लोगों की गिरफ्तारी और कार्रवाई का उल्लेख मिलता है। यदि सचिन के इन तीन मामलों को भी अलग कार्रवाई के रूप में जोड़ा जाए तो आंकड़ा 36 तक पहुंचता है। इन आंकड़ों का पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान जरूरी है, ताकि दोहरी गणना की संभावना समाप्त हो सके।

सवाल यह है कि आखिर बिना डिग्री के लोग वर्षों तक क्लीनिक कैसे चलाते रहते हैं? पांडेसरा में पकड़े गए कुछ आरोपी दो से तीन दशक तक कथित रूप से चिकित्सा करते रहे। किसी ने कंपाउंडर का काम किया तो किसी ने अस्पताल में सहायक के रूप में अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं को डॉक्टर बताकर क्लीनिक शुरू कर दिए। गरीब और प्रवासी मजदूरों की बड़ी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे क्लीनिकों को मरीज भी मिल जाते हैं। कम फीस, नजदीकी स्थान और तत्काल उपचार का भरोसा लोगों को वहां पहुंचा देता है। यही मजबूरी कुछ अपात्र लोगों के लिए कमाई का जरिया बन जाती है। कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान मौजूद है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 34 के अनुसार राज्य या राष्ट्रीय मेडिकल रजिस्टर में पंजीकृत व्यक्ति ही योग्य आधुनिक चिकित्सा चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस कर सकता है। इसका उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक की कैद अथवा पांच लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1963 की धारा 30 भी अपंजीकृत व्यक्तियों को चिकित्सा करने से रोकती है। इसके तहत पहली बार अपराध सिद्ध होने पर 500 रुपये तक जुर्माने, दूसरी बार छह महीने तक कैद और 500 रुपये तक जुर्माने तथा बाद के अपराधों में दो वर्ष तक कैद और 2,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि अलग-अलग कानूनों की प्रयोज्यता मामले के तथ्यों और संबंधित चिकित्सा पद्धति पर निर्भर करती है। इसके बावजूद झोलाछाप डॉक्टरों का कारोबार समाप्त नहीं हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण गिरफ्तारी और सजा के बीच लंबी कानूनी प्रक्रिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन दोषी साबित करने के लिए अदालत में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। मेडिकल अधिकारियों की रिपोर्ट, डिग्री और पंजीकरण का सत्यापन, गवाहों के बयान तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में समय लगता है। कई मामलों में जांच और न्यायिक सुनवाई लंबी खिंच जाती है। दूसरी ओर, पुराने मामलों में कार्रवाई होने के बावजूद आरोपियों की दोबारा गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी नहीं हो पाती। पांडेसरा में पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आना इसी समस्या की ओर संकेत करता है। सूरत प्रशासन को अब केवल छापेमारी और गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शहर के पांडेसरा, डिंडोली, सचिन, उधना, लिंबायत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित सभी क्लीनिकों का नियमित सत्यापन होना चाहिए। चिकित्सकों की डिग्री, पंजीकरण और क्लीनिक के संचालन की अनुमति की जांच अनिवार्य होनी चाहिए। पुराने मामलों की समीक्षा कर दोषियों के खिलाफ न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाए। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे क्लीनिकों के दोबारा खुलने पर भी नजर रखनी होगी।

राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित अनेक राज्यों में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आती रहती हैं।

थाली पर बाजार का कब्जा, इलाज के नाम पर नया कारोबार

-महेंद्र कुमार कुशवाह-

भारत की थाली में आया बदलाव केवल खानपान की आदतों का परिवर्तन नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाजार के बढ़ते वर्चस्व की कहानी है। जिस भोजन को कभी शरीर, प्रकृति और ऋतु के बीच संतुलन का माध्यम माना जाता था, वह धीरे-धीरे औद्योगिक उत्पादन और मुनाफे का उत्पाद बन गया। खेतों से सीधे रसोई तक पहुंचने वाले अनाज, दालें, सब्जियां और पारंपरिक खाद्य पदार्थ अब चमकदार पैकेटों, इंस्टेंट फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बाजार ने सुविधा के नाम पर हमारी थाली में जगह बनाई और धीरे-धीरे हमारी भूख तथा पसंद पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।

इसका परिणाम हमारे सामने है। देश एक ऐसे विरोधाभास से गुजर रहा है, जहां करोड़ों लोग कुपोषण और पोषण संबंधी कमियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, फैटी लिवर और हृदय संबंधी बीमारियां तेजी से सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती बन रही हैं। यह केवल व्यक्तिगत जीवनशैली का संकट नहीं, बल्कि उस खाद्य व्यवस्था का परिणाम भी है जिसमें सस्ता, सुविधाजनक और आक्रामक ढंग से प्रचारित भोजन अक्सर पौष्टिक विकल्पों पर भारी पड़ता है।

भारतीय संदर्भ में यह संकट और भी गंभीर है। दक्षिण एशियाई आबादी में अपेक्षाकृत कम बीएमआई पर भी पेट के आसपास वसा जमा होने और मेटाबॉलिक जोखिम बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है। यानी सामान्य दिखने वाला शरीर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप-2 डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी समस्याओं की गिरफ्त में हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हमारी स्वास्थ्य नीतियां इस बदलते खतरे को उतनी गंभीरता से समझ रही हैं, जितनी जरूरत है?

इसी संकट के बीच जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं ने दुनिया भर में नई उम्मीद और नया बाजार दोनों पैदा किए हैं। ये दवाएं भूख और तृप्ति से जुड़े जैविक संकेतों को प्रभावित करती हैं तथा चिकित्सकीय निगरानी में वजन घटाने में प्रभावी साबित हुई हैं। मोटापे के उपचार में इनकी भूमिका को नकारना वैज्ञानिक उपलब्धियों से आंखें मूंदने जैसा होगा। लेकिन किसी दवा की सफलता को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सफलता मान लेना भी बड़ी भूल है।

भारत जैसे देश में सबसे बड़ा सवाल इन दवाओं की कीमत, पहुंच और दीर्घकालिक उपयोग का है। जब स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा आज भी लोगों की जेब से खर्च होता है, तब महंगी दवाओं पर आधारित मोटापा नियंत्रण का मॉडल कितनी आबादी तक पहुंच पाएगा? क्या यह समाधान उन परिवारों के लिए भी उपलब्ध होगा, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन, शिक्षा और बुनियादी जरूरतों में खर्च हो जाता है? हम मोटापे को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का बाजार तो विकसित कर रहे हैं, लेकिन मोटापा पैदा करने वाली खाद्य परिस्थितियों को बदलने के लिए उतनी ही इच्छाशक्ति दिखा पा रहे हैं?

यहीं इस बहस का सबसे असहज पहलू सामने आता है। एक तरफ खाद्य उद्योग ऐसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर प्रचार करता है जिनमें अतिरिक्त चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा की भूमिका होती है। दूसरी तरफ खराब खानपान से जुड़े बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों का इलाज एक नए व्यावसायिक अवसर में बदल रहा है। यह कहना गलत होगा कि हर मोटापा किसी एक खाद्य पदार्थ या कंपनी के कारण होता है, लेकिन यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि खाद्य वातावरण और आक्रामक विपणन का लोगों की पसंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

मोटापे को केवल आलस्य, अनुशासनहीनता या कमजोर इच्छाशक्ति का परिणाम बताना समस्या को सुविधाजनक ढंग से व्यक्ति के सिर मढ़ देना है। भोजन की उपलब्धता, उसकी कीमत, विज्ञापन, शहरी जीवनशैली और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब बच्चों को आकर्षक पैकेजिंग, कार्टून चरित्रों और विज्ञापनों के माध्यम से कम उम्र से ही जंक फूड की ओर आकर्षित किया जाता है, तब उनकी खानपान संबंधी पसंद को पूरी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का परिणाम कैसे माना जा सकता है?

इस संदर्भ में डेनिश वैज्ञानिक लोटे ब्येरे नुडसन की टिप्पणी विशेष रूप से विचारणीय है। जीएलपी-1 विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नुडसन ने मानव शरीर की विकासवादी संरचना और आज के खाद्य वातावरण के बीच बढ़ते अंतर की ओर ध्यान दिलाया था। उनका तर्क था कि मानव शरीर भोजन की कमी और कठिन उपलब्धता वाले वातावरण में विकसित हुआ, जबकि आज उसे हर जगह उपलब्ध अत्यधिक प्रसंस्कृत और स्वाद-उत्तेजक खाद्य पदार्थों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने खाद्य उद्योग की जनस्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी का सवाल भी उठाया। यह टिप्पणी आधुनिक खाद्य अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। फूड साइंटिस्ट श्रीमंत वैभव साठे कहते हैं हमारा शरीर प्राकृतिक चीजें खाने के लिए ही बना है। प्रकृति ने हमें आलू दिया और हम उसे उबालकर खाने की बजाए चिप्स बनाकर खाने लगे। चने की जगह हमने बेसन से सेंव बना ली। जब हम ताजा खा सकते हैं तो फिर पैकेटबंद खाना क्यों खा रहे हैं ।

भारत में इसका जवाब केवल उपभोक्ता जागरूकता अभियानों से नहीं मिलेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की भूमिका केवल उत्पादों के लाइसेंस और नमूनों की जांच तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। खाद्य उत्पादों की पोषण संबंधी जानकारी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अतिरिक्त चीनी, नमक और संतृप्त वसा की अधिक मात्रा वाले उत्पादों पर प्रभावी चेतावनी व्यवस्था, बच्चों को लक्षित भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण और स्कूलों में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के प्रचार पर सख्ती समय की मांग है।

सरकार को मोटे अनाज, दालों, मौसमी फल-सब्जियों और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों को केवल प्रचार अभियानों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इन्हें आम परिवार की पहुंच में सस्ता और सहज उपलब्ध कराना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्कूल पोषण कार्यक्रमों में भोजन की गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी होगी। स्वस्थ भोजन महंगा और अस्वस्थ भोजन सस्ता रहेगा, तो केवल जागरूकता के भाषणों से खानपान की तस्वीर नहीं बदलेगी।

नई दवाएं विज्ञान की उपलब्धि हैं और जरूरतमंद मरीजों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन दवा उस व्यवस्था का विकल्प नहीं बन सकती जो बीमारी के जोखिम को लगातार बढ़ा रही है। जीएलपी-1 दवाओं के संभावित दुष्प्रभाव, उपचार की उपयुक्तता और दवा बंद करने के बाद वजन दोबारा बढ़ने की आशंका जैसे पहलुओं पर चिकित्सकीय निगरानी जरूरी है। इन्हें संतुलित पोषण, शारीरिक गतिविधि और व्यापक मोटापा प्रबंधन से अलग करके देखना उचित नहीं होगा।

असल सवाल यह नहीं है कि भारत मोटापे के इलाज के लिए कितनी नई दवाएं खरीद सकता है। सवाल यह है कि भारत अपने नागरिकों को बीमार करने वाले खाद्य वातावरण को बदलने के लिए कितना तैयार है। जिस देश की युवा आबादी को भविष्य की आर्थिक ताकत बताया जा रहा है, यदि वही आबादी कम उम्र में मधुमेह, हृदय रोग और मेटाबॉलिक विकारों की गिरफ्त में आने लगे, तो जनसांख्यिकीय लाभांश का दावा भी खोखला साबित होगा। किसी राष्ट्र की प्रगति का पैमाना केवल अर्थव्यवस्था का आकार, बाजार का विस्तार या दवा उद्योग का कारोबार नहीं हो सकता। यह भी देखना होगा कि उसकी थाली में क्या परोसा जा रहा है और उस भोजन की कीमत आने वाली पीढ़ियां अपने स्वास्थ्य से तो नहीं चुका रही हैं। बीमारी के बाद इलाज बेचना बाजार का कारोबार हो सकता है, लेकिन बीमारी पैदा करने वाली परिस्थितियों को रोकना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है।

विकास की रफ्तार के सामने विपक्ष की सियासत मोदी के समर्थन में उठती आवाजों ने बढ़ाई राजनीतिक चुनौती

-कांतिलाल मांडोत-

भारतीय राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यह संघर्ष विकास की दिशा और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के रूप में दिखाई देने लगा है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और सरकार को घेरने के लिए लगातार नए मुद्दों की तलाश में जुटा है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता की अपेक्षा है कि राजनीतिक विरोध के साथ देशहित और विकास के मुद्दों को भी प्राथमिकता दी जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा इसी राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बनासकांठा में लगभग 14 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की प्राथमिकता गांव, किसान, युवा और महिलाओं का सशक्तीकरण है। विशाल खाट सभा में उमड़ी भीड़ और समर्थकों का उत्साह भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना। प्रधानमंत्री ने आयोजकों की व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे अपनी संबोधित की गई सबसे बड़ी खाट सभाओं में से एक बताया। गुजरात की धरती से दिया गया उनका संदेश केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक दिशा का संकेत भी देता दिखाई दिया।

बनासकांठा में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यहां का आलू दुनिया में प्रसिद्ध है और किसानों को आलू से सोना बनाने का दावा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां के किसान अपनी मेहनत से समृद्धि पैदा कर रहे हैं। इस टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करते हुए लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने का प्रयास है।

प्रधानमंत्री ने गुजरात में चार हजार से अधिक आधुनिक आंगनवाड़ियों की शुरुआत का उल्लेख करते हुए बताया कि इससे लगभग चार लाख बच्चों और गर्भवती माताओं को लाभ मिलेगा। अहमदाबाद-मेहसाणा राजमार्ग को चार लेन से आठ लेन करने की घोषणा भी आधारभूत संरचना के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विकास की यही अवधारणा है, जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कल्याण को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

इस दौरे के दौ

संक्षिप्त समाचार

भीम स्टेडियम के लिए 50 करोड़ देने पर सांसद धर्मबीर सिंह ने सीएम सैनी का जताया आभार, बॉक्सिंग एक्सीलेंस सेंटर की रखी मांग



अनप्लग इंडिया

भिवानी। सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने भीम स्टेडियम को आधुनिक खेल सुविधाओं और उपकरणों से अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह खिलाड़ियों के लिए एक 'बॉक्सिंग एक्सीलेंस सेंटर' और चोट के इलाज के लिए एक केंद्र की भी मांग करेंगे। सांसद धर्मबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'हरियाणा में खिलाड़ियों को मिलने वाले नकद पुरस्कार शायद देश के किसी अन्य राज्य में इतने अधिक नहीं हैं। यही वजह है कि दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी हरियाणा की खेल नीति से प्रभावित होकर यहां अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। एक लड़की का जन्म राजस्थान में हुआ था और उसकी शादी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुई। उसके माता-पिता ने भी कई बार मुझसे अनुरोध किया कि आखिर उनका कसूर क्या है? उनकी बेटी की शादी हरियाणा में हुई है, लेकिन उसकी पढ़ाई राजस्थान में हुई थी, इसलिए उसका नाम हरियाणा की सूची में शामिल नहीं है। आज दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी यह प्रयास करते हैं कि किसी तरह उनका नाम हरियाणा में दर्ज हो जाए। यह सब हरियाणा की खेल नीति का परिणाम है।' सांसद ने आगे कहा, 'समय के साथ हर चीज पुरानी होती है और भीम स्टेडियम की उम्र का असर दिखाई देने लगता है। स्टेडियम की सीढ़ियां भी अब टूटने लगी हैं। खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों से पूछकर जरूरत की चीजों की लिस्ट बनाई गई। इसके बाद इस खेल विभाग के अधिकारियों द्वारा इस्टीमेट बनाकर हरियाणा सरकार को भेजा था। इस पर मुख्यमंत्री ने एकमुश्त 50 करोड़ रुपए भीम स्टेडियम को आधुनिक खेल सुविधाओं और उपकरणों के लिए मंजूर की है। इस कदम से खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलेगा। जिले में जब सुविधाएं मिल जाएंगी तो खिलाड़ी कॉमनवेल्थ, एशियाड या ओलंपिक में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

सांसद ने कहा कि हमने 'बॉक्सिंग एक्सीलेंस सेंटर' की सरकार से मांग की है। उम्मीद है कि यह मांग जल्द पूरी होगी। चोट के इलाज के लिए एक केंद्रीय स्वास्थ्य और खेल मंत्री को पत्र लिखा है।

समाधान शिविर में एसडीएम ने 10 में से अधिकांश शिकायतों का मौके पर कराया समाधान



अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार के निर्देश और डीसी उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नियमित रूप से समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को स्थानीय स्तर पर आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम हितेंद्र कुमार ने लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों के समयबद्ध निपटारे के कड़े निर्देश दिए।

एक ही छत के नीचे मिल रहा समाधानःएसडीएम हितेंद्र कुमार ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का सरल और त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। सोमवार को आयोजित इस शिविर में बिजली, पानी, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) और बुढ़ापा सम्मान भत्ता पेंशन से जुड़े विभिन्न मामले प्रमुखता से सामने आए।?

शिविर के दौरान कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुईं। अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया। वहीं, शेष बची शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर तय समय सीमा के भीतर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक साथ बैठकर जनता की समस्याएं सुनते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त सपना यादव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

गुरुग्राम में बाजरा खरीद जारी: मंडियों में अब तक 41,252 मीट्रिक टन की आवक



अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। जिले में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान बाजरे की सरकारी खरीद की प्रक्रिया बेहद सुचारू और पारदर्शी ढंग से चल रही है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम की विभिन्न अनाज मंडियों में अब तक कुल 41,252 मीट्रिक टन बाजरे की आवक दर्ज की जा चुकी है।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए जिले की तीन प्रमुख मंडियों, जटौली, फर्रुखनगर और सोहना में खरीद का कार्य तेजी से जारी है। अब तक फर्रुखनगर मंडी में 10 हजार मीट्रिक टन, जटौली मंडी में सबसे अधिक 26,488 मीट्रिक टन तथा सोहना मंडी में 4,764 मीट्रिक टन बाजरे की आवक दर्ज की गई है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से बाजरा उत्पादक किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। योजना के अंतर्गत बाजरे के लिए 2,900 रूपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया गया है। निर्धारित नियमों एवं पात्रता के अनुसार, मंडी में बिक्री मूल्य और एमएसपी के बीच अधिकतम 600 रूपए प्रति क्विंटल तक के अंतर की भरपाई राज्य सरकार द्वारा सीधे किसानों के खाते में भावांतर के रूप में की जाएगी। प्रशासन की ओर से मंडियों में पेयजल, शेड और तौल की पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

हरियाणा की प्रगति और जनता की खुशहाली हमारी साझा मंजिल : नायब सिंह सैनी

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक राहें और विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हरियाणा की प्रगति और प्रदेश के लोगों की खुशहाली सभी की साझा मंजिल है। हम सभी की पहचान इस बात से है कि हम हरियाणा की जनता के प्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझते हुए प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री सोमवार को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा विधानसभा द्वारा संविधान पखवाड़े के तहत आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हीरक जयंती के इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति से इसकी गरिमा बढ़ी है और संसदीय प्रक्रियाओं, सदन की मर्यादा तथा जनप्रतिनिधियों के दायित्वों पर उनका मार्गदर्शन सभी के लिए मूल्यवान है। उन्होंने



कहा कि हीरक जयंती समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने पधार कर हरियाणा की जनता को अपना आर्शीवाद दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की 60 वर्षों की विकास यात्रा केवल सड़कों, संस्थानों और उद्योगों के विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों की मेहनत भी शामिल है। खेतों की हरियाली से उद्योगों की ऊंचाइयों तक, गांवों की पगडंडियों से आधुनिक एक्सप्रेस-वे तक और अखाड़ों की मिट्टी से विश्व के खेल मंचों तक हरियाणा ने अपने परिश्रम, साहस और संकल्प से प्रगति के नए अध्याय लिखे हैं। प्रदेश की उपलब्धियों की नींव उन चर्चाओं, निर्णयों और कानूनों से भी पड़ी है, जिन्हें जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा में आकार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर, 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था और उस समय विधानसभा में 54 सदस्य थे। वर्ष 1967 में विधानसभा सीटों की संख्या 81 हुई और वर्ष 1977 में बढ़कर 90 हो गई। उन्होंने कहा कि इन सीटों में आज बढ़ोतरी की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो सके और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश 15वीं विधानसभा के दौर में अपनी लोकतांत्रिक यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये आंकड़े प्रतिनिधित्व के विस्तार और जनता की आकांक्षाओं के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर, 1966 को हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। उस समय संसाधन सीमित थे और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, सड़क तथा प्रशासनिक व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना बड़ी चुनौती थी। उन्होंने उन सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने इन परिस्थितियों में प्रदेश के भविष्य की मजबूत नींव रखने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान हमारे निर्णयों और आचरण में दिखाई देना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श निहित हैं। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन आदर्शों को शासन के व्यवहार में उतारें। जब पात्र नागरिक को बिना भेदभाव उसका अधिकार मिलता है, कमजोर व्यक्ति की सुनवाई होती है और समाज में परस्पर सम्मान बढ़ता है, तभी इन संवैधानिक मूल्यों को मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा कानून बनाने, सार्वजनिक धन के उपयोग को स्वीकृति देने और सरकार को जवाबदेह बनाने का महत्वपूर्ण मंच है। सदन में उठाया गया सार्थक प्रश्न किसी गांव की समस्या को समाधान तक पहुंचा सकता है और किसी विधेयक पर दिया गया उपयोगी सुझाव लाखों नागरिकों का जीवन बेहतर बना सकता है। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, बजट चर्चा और समितियों का कार्य संसदीय व्यवस्था को जीवंत बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं का प्रभावी उपयोग करने के लिए अध्ययन, तैयारी और जनता से निरंतर संपर्क आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जवाबदेही शासन को मजबूत बनाती है। विपक्ष द्वारा उठाई गई जनहित की बात को गंभीरता से सुनना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। इसी प्रकार आलोचना के साथ व्यावहारिक सुझाव देना भी सार्वजनिक जीवन की बड़ी सेवा है। सदन में तीखी बहस हो सकती है, लेकिन भाषा की गरिमा बनी रहनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को तर्कों से एक-दूसरे के विचारों को चुनौती देनी चाहिए और अपने आचरण से लोकतंत्र तथा संविधान के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज डिजिटल माध्यमों से नागरिक जनप्रतिनिधियों के शब्दों और व्यवहार को तुरंत देखते हैं। विशेष रूप से युवा पीढ़ी उनसे सीखती है कि सार्वजनिक जीवन में असहमति कैसे व्यक्त की जाती है।

केंद्र सरकार को महाराजा अग्रसेन जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए- बजरंग गर्ग

अनप्लग इंडिया

फतेहाबाद- वैश्य समाज की मीटिंग अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में सामाजिक संस्था ताली कीर्तन पार्टी को समाज द्वारा अग्रोहा धाम में सम्मानित किया गया। अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि वैश्य समाज के व्यक्ति देश भर में महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र व जनता की सेवा में लगे हुए हैं। महाराजा अग्रसेन ने समाजवाद को बढ़ावा देते हुए गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया। महाराजा अग्रसेन ने जरूरतमंद को हर घर से एक ईंट एक मुद्रा देने की परंपरा अपने राज्य में लागू की, जिसे युगों-युगों तक याद किया जाएगा। बजरंग गर्ग ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी का महल 125 एकड़ में अग्रोहा में बना हुआ था। वह अब टीलों के रूप में बदल चुका है। सरकार को अग्रोहा धाम टीलें की खुदाई का काम धीमी गति से करने की बजाय उसमें तेजी लानी चाहिए। टीलें की खुदाई में बेशुमार कीमती सामान मिलने की उम्मीद है क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी। श्री गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम में महाराज अग्रसेन जी के नाम पर करोड़ों रुपए की लागत से दो म्यूजियम बनाए गए हैं। जिसमें महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को दर्शाया जाएगा ताकि देश की युवा पीढ़ी महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी के बारे में जानकारी लेकर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र व जनता के हित में कार्य कर सकें। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को महान पुरुष महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर फतेहाबाद जिले में यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए और केंद्र सरकार को महाराजा अग्रसेन जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए। सरकार



को हरियाणा में स्कूल, कॉलेज व हॉस्पिटल को महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर बनाने चाहिए। जिसे जनता में जागरुकता आएगी और हर नागरिक सामाजिक व धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देगा।इस अवसर पर अग्रवाल संगठन प्रधान ब्रह्मानंद गोयल, ताली कीर्तन मंडली प्रधान सज्जन अग्रवाल, अनूप मित्तल, सोनू बागड़ी, नरेश गोयल, मांगेराम माचरा, बिट्टू गर्ग, चंद्र शर्मा, रोशन जोशी, राजेश गर्ग, आनंद गर्ग,सुशील अग्रवाल, नवीन गर्ग, साहिल अग्रवाल, हर्ष गोयल, पवन ढाकर, संदीप बंसल, आनीष, बिट्टू बंसल, ललित बंसल, अमित मित्तल, बजरंग गोयल, ऋतिक अग्रवाल आदि प्रतिनिधि मौजूद रहे।

यमुनानगर में बाल-बाल बचे एसडीएम, डंपर ड्राइवर ने कुचलने की कोशिश की थी

अनप्लग इंडिया

यमुनानगर । हरियाणा के यमुनानगर जिले में पुलिस ने अवैध माइनिंग में शामिल एक डंपर के ड्राइवर के खिलाफ व्यासपुर के एसडीएम को कुचलने की कोशिश के मामले में केस दर्ज किया है। फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक, व्यासपुर के एसडीएम डॉ. कुलदीप सिंह ने 31 अक्टूबर की सुबह हुई इस घटना के बारे में सधौरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में एसडीएम ने कहा कि वह सुबह करीब 6.15 बजे 'रन फॉर यूनिटी' प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सधौरा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जा रहे थे, तभी उन्होंने रेस्ट हाउस के पास एक डंपर ट्रक देखा। डंपर की नंबर प्लेट धुंधली थी, और एसडीएम को शक था कि उसमें गैर-कानूनी तरीके से माइन का सामान ले जाया जा रहा है। उन्होंने ड्राइवर को इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी रोकने का इशारा किया। लेकिन, ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी तेज कर दी और एसडीएम को कुचलने के इरादे से सीधे उनकी ओर डंपर ले जाने की



कोशिश की। डॉ. सिंह बाल-बाल बच गए और गाड़ी का पीछा करने से पहले तुरंत पुलिस को बताया।

पीछा करते समय, एक सफेद कार, जो डंपर का पीछा कर रही थी, ने एसडीएम की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि कार ड्राइवर ने जानबूझकर गलत तरीके से गाड़ी चलाई और अचानक ब्रेक लगाकर एसडीएम का रास्ता रोका, जिससे डंपर ड्राइवर मौके से भाग गया।

एसडीएम ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली। सढौरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज लखविंदर सिंह ने कहा कि एसडीएम की शिकायत के आधार पर डंपर ड्राइवर और कार में बैठे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामला संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, और पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या डंपर में गैर-कानूनी तरीके से माइन किया गया सामान ले जाया जा रहा था और क्रेटा में बैठे लोगों ने गाड़ी को भागने में मदद की थी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

किसान कीटनाशकों का प्रयोग वैज्ञानिकों की सलाह और संतुलित मात्रा में करें: प्रो. बलदेव राज काम्बोज

अनप्लग इंडिया

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग द्वारा कोरटेवा एग्रीसाइंस के प्रायोजन से किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित, जिम्मेदार एवं विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कीटनाशक फसलों को कीटों और रोगों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा वैज्ञानिकों की सलाह और निर्धारित मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। बिना जरूरत और अधिक मात्रा में कीटनाशकों का छिडक़ाव करने से खेती की लागत बढ़ती है तथा फसल, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि कीटनाशक खरीदते और इस्तेमाल करते समय उसके पैकेट या बोतल पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। छिडक़ाव करते समय मास्क, दस्ताने और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों का गलत इस्तेमाल



मिट्टी, पानी, पशु-पक्षियों और लाभकारी कीटों के लिए भी हानिकारक होता है। प्रो. काम्बोज ने कहा कि समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) टिकाऊ खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसानों को कीटों से बचाव के लिए केवल रासायनिक दवाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए खेतों की नियमित निगरानी, कीटों की सही पहचान, जैविक नियंत्रण, फेरोमोन ट्रैप और कीट प्रतिरोधी किस्मों जैसे उपाय अपनाने चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों का छिडक़ाव वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार संतुलित मात्रा में करना चाहिए, इससे खेती की लागत कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय लगातार नवीनतम तकनीकें और सुरक्षित खेती के तरीकों की जानकारी निरंतर किसानों तक पहुंचा रहा है। इसके लिए किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता शिविरों, किसान गोष्ठियों और खेतों में प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों से आह्वान किया कि वे किसानों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और उन्हें सही जानकारी देकर टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दें। अनुसंधान निदेशक डॉ. राजबीर गर्ग ने कहा कि किसानों को कीटनाशकों का प्रयोग करने से पहले फसल और उसमें लगने वाले कीट की सही पहचान करनी चाहिए। इसके बाद ही कृषि वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवा का चयन और छिडक़ाव करना चाहिए। उन्होंने किसानों से सुरक्षित कीटनाशक उपयोग अपनाने तथा पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉ. सुनीता यादव ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया और विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। कोरटेवा एग्रीसाइंस के प्रतिनिधि डॉ. बसवेश्वर घोडक़ी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंच संचालन डॉ. रीना चौहान ने किया। कोरटेवा एग्रीसाइंस द्वारा प्रतिभागियों को सेफ्टी किट भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर कीट विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी तथा किसान उपस्थित रहे।

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जनता की एकजुटता महत्वपूर्ण संदेश : कुमारी सैलजा

अनप्लग इंडिया

सिरसा। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य कुमारी सैलजा ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने यह संदेश दिया है कि देश की जनता अपने मताधिकार, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को लेकर सजग है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आयोजित महारैली ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को प्रमुखता से सामने रखा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का संतोषजनक जवाब मिलना लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही तय करने और नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग दोहराई। सांसद ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष किसी संस्था को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए है। लोकतंत्र में जनता का विश्वास सर्वोपरि है और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुमारी सैलजा ने हरियाणा, उत्तराखंड सहित देशभर से महारैली में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस अपनी आवाज सड़क से संसद तक शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से उठाती रहेगी। सांसद ने कहा कि हमारा संकल्प स्पष्ट है मताधिकार सुरक्षित रहेगा, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा।



5 नवंबर को अमित शाह करेंगे 1857 के शहीद स्मारक का लोकार्पण, अनिल विज ने लिया तैयारियों का जायजा

अनप्लग इंडिया

अंबाला। अंबाला छावनी में 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक के 5 नवम्बर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन को लेकर अम्बाला जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में शहीद स्मारक में बैठक हुई जिसमें सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव के. मकरंद पांडुरंग के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने शहीदी स्मारक का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बैठक के दौरान कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इससे पहले आयुक्त एवं सचिव के मकरंद पांडुरंग ने शहीदी स्मारक के उद्घाटन से संबंधित कार्यक्रम की तैयारियों एवं विभिन्न



व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 5 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने तथा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को गंभीरता एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियों को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने गांधी ग्राउंड का दौरा किया

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज प्रातः अम्बाला छावनी के गांधी ग्राउंड का दौरा कर आगामी 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उपायुक्त सचिन गुप्ता भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर बनाए जा रहे मुख्य मंच, बैठने की व्यवस्था, कलाकारों के लिए मंच, मीडिया गैलरी तथा पार्किंग व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिजली, पेयजल तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अम्बाला छावनी में निर्मित आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक-1857 का लोकार्पण करेंगे और गांधी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह शहीद स्मारक 1857 की क्रांति के वीर शहीदों और गुमनाम क्रांतिकारियों के बलिदान को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि लगभग 22 एकड़ में फैले इस स्मारक में 1857 की क्रांति से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों को 22 गैलरियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। स्मारक में लगभग 700 शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों के योगदान और बलिदान से परिचित हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसभा में आने वाले लोगों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू आवागमन को प्राथमिकता देते हुए सभी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जाएं।

इस मौके पर उपायुक्त सचिन गुप्ता, सीईओ जिला परिषद् गगनदीप सिंह, एडीपीआर मनीष लौहान, शहीद स्मारक के निदेशक डॉ कुलदीप सैनी, एसडीएम नारायणगढ़ शिवजीत भारती, संयुक्त निदेशक नीरज कुमार, अधीक्षक अभियन्ता भूपेन्द्र, कार्यकारी अभियन्ता रितेश अग्रवाल, कार्यकारी अभियन्ता नवीन राठी के साथ-साथ सम्बधिंत विभागों के अधिकारीगण व एजेन्सी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

संक्षिप्त डायरी

एसआईआर को लेकर कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, घुसपैठियों पर कही बड़ी बात

अनप्लग इंडिया



वाराणसी। लोकसभा सांसद संबित पात्रा सोमवार को वाराणसी पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने एसआईआर पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि देश में घुसपैठिए हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कहती है कि देश के रिसोर्सेज के ऊपर भारतवर्ष के संसाधनों के ऊपर यदि पहला हक किसी का है तो वो भारतीयों का है। कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि भारतवर्ष के संसाधनों के ऊपर यदि पहला हक किसी का है तो घुसपैठियों का है। घुसपैठियों के नंबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है, पूरा घुसपैठियों के विषय में भर्ती कराया गया है। ये जो प्रक्रिया एसआईआर की चल रही है, जो 70 साल में जो स्वतंत्रता से लेकर अब तक चल रहा था, आसाम में क्या हुआ, आधा आसाम घुसपैठियों से भर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो आसाम में घुसपैठियों का खुलासा कर रही है। एसआईआर में घुसपैठिए कभी भी वोटर नहीं बन सकते हैं। यह काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। कांग्रेस और सपा पार्टी नहीं करेगी।

कोलकाता रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज, फरक्का लॉक गेट से होकर पहुंचेगा बंगाल

अनप्लग इंडिया



वाराणसी। काशी की गंगा में विदेशी पर्यटकों को सैर कराने के बाद लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास रविवार को सुबह 11 बजे 16 पर्यटकों को लेकर कोलकाता के लिए रवाना हो गया। वाराणसी से कोलकाता तक का सफर 19 रात और 20 दिनों का होगा। क्रूज 18 नवंबर को कोलकाता पहुंचेगा। इस दौरान पर्यटक गंगा के तट पर बसे ऐतिहासिक शहरों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे। क्रूज संचालक राज सिंह ने बताया कि गंगा विलास 27 अक्तूबर को 15 विदेशी पर्यटकों के साथ रामनगर स्थित मल्टीमॉडल टर्मिनल पहुंचा था। काशी में पर्यटकों के लिए गंगा आरती, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों के भ्रमण कराया गया। रविवार को सुबह 11 बजे रामनगर स्थित बंदरगाह से कोलकाता के लिए निकला है। क्रूज यहां से आगे की यात्रा में गाजीपुर, बक्सर और पटना सहित बिहार के विभिन्न पड़ावों से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा। फरक्का लॉक गेट से होते हुए पहुंचेगा बंगाल बिहार के बाद क्रूज फरक्का लॉक गेट पार कर हुगली नदी के जलमार्ग से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा। इसके बाद जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, मटियारी और कालना जैसे स्थानों पर भ्रमण प्रस्तावित है। मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी पैलेस और कटर मस्जिद, जबकि कालना में 108 शिव मंदिरों वाला राजबाड़ी मंदिर परिसर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। मटियारी में पारंपरिक धातु शिल्प से जुड़े कारीगरों को देखने का अवसर भी मिलेगा। यात्रा के अंतिम चरण में क्रूज कोलकाता पहुंचेगा।

सवा लाख दीपों से जगमगाएगा शृंगवेरपुरधाम



अनप्लग इंडिया

प्रयागराज। भगवान श्रीराम की पावन तपोभूमि शृंगवेरपुरधाम में छह नवंबर से आठ नवंबर तक सातवां शृंगवेरपुर महोत्सव आयोजित होगा। इस बार अयोध्या और चित्रकूट की तर्ज पर सवा लाख दीपों का भव्य दीपोत्सव होगा। महोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। यह तीन दिवसीय महोत्सव दिवाली की पूर्व संध्या पर धनतेरस के दूसरे दिन आयोजित होगा। गंगा तट सहित पूरे शृंगवेरपुरधाम में सवा लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। महोत्सव का आयोजन जय श्रीराम सेवा समिति शृंगवेरपुरधाम कर रही है। समिति के अध्यक्ष संजय तिवारी और संचालक अरुण द्विवेदी आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को आमंत्रण दिया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी निमंत्रण भेजा गया है। आमंत्रित अतिथियों ने महोत्सव में आने का आश्वासन दिया है। महोत्सव के अन्य कार्यक्रम तीन दिवसीय महोत्सव में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे। विभिन्न सरकारी विभाग आकर्षक प्रदर्शनियां लगाएंगे। इन प्रदर्शनियों में योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। आयोजकों का उद्देश्य शृंगवेरपुरधाम को राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनाना है। कुम्हारों में खासा उत्साह दीपोत्सव को लेकर कुम्हारों में भी खासा उत्साह है। दीपदान के लिए बड़ी संख्या में मिट्टी के दीये तैयार किए जा रहे हैं। कुम्हार दिन-रात दीये बनाने में लगे हुए हैं, ताकि दीपोत्सव के दिन पूरा तीर्थक्षेत्र दीपों की रोशनी से जगमगा उठे।

रामगंगा चौबारी मेले की तैयारी शुरू, 21 से 28 नवंबर तक होगा आयोजन, प्रबंधन समिति का किया जाएगा गठन



एजेंसी

बरेली। रामगंगा नदी के किनारे चौबारी गांव में लगने वाले पारंपरिक कार्तिक मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार मेला 21 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मेले के आयोजन और व्यवस्थाओं के संचालन के लिए प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लोगों से 12 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। उपजिला मजिस्ट्रेट एवं मेला मजिस्ट्रेट सदर इशिता किशोर ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी चौबारी में रामगंगा नदी के किनारे कार्तिक मेला आयोजित होगा। मेले का प्रबंधन ग्राम चौबारी के लोगों की ओर से गठित समिति करती है। समिति में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक मेला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर नियमानुसार प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। समिति को मेले से संबंधित समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी। आवेदन और अन्य जानकारी के लिए नायब तहसीलदार चौबारी, तहसीलदार सदर या मेला मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है।

त्योहार बीता, मिठाई पची, फिर आई रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा तंत्र की सुस्ती से मिलावटखोरों की चांदी

अनप्लग इंडिया



वाराणसी। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर नकेल कसने का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का दावा सिर्फ रस्म अदायगी साबित हो रहा है। बीते अगस्त माह में रक्षाबंधन के अवसर पर शहर में 31 जगहों से लिए गए सैंपल में से 13 की जांच रिपोर्ट दिवाली तक भी नहीं आ सकेगी। जिन छह नमूनों की रिपोर्ट फेल आई, उनमें अब तक जुमार्ना तय नहीं किया गया। दो माह पहले रक्षाबंधन पर नष्ट कराई गई 523 किलो दूषित मिठाई और खोया के मामले में भी संबंधित कारोबारियों पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। खाद्य व्यापार मंडल के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में छोटी-बड़ी करीब 2200 से अधिक मिठाई और डेयरी उत्पाद की दुकानें संचालित हैं। दिवाली पर यहां पांच दिनों में करीब 25 हजार क्विंटल मिठाई की खपत होती है। इसके विपरीत, निगरानी के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के पास बुनियादी ढांचा और पर्याप्त मानव संसाधन तक नहीं हैं। चंद टीमों के भरोसे पूरे जिले की निगरानी का दावा किया जाता है। विभागीय लचरता की स्थिति यह है कि अभियान केवल मुख्य सड़कों की गिनी-चुनी दुकानों और चौराहों तक सिमट कर रह जाता है, जबकि घनी बस्तियों और ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से केमिकल युक्त मावा और सिंथेटिक पनीर खपाया जा रहा है। न जुमार्ने का डर, न कार्रवाई की चिंता रक्षाबंधन के दौरान विभाग ने करौंदी, खालिसपुर और मिल्कीचक समेत कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर 523 किलो सड़ी-गली रसभरी, बूंदी के लड्डू और संदिग्ध खोया नाले में फिकवाया था। विभाग ने तब दावा किया था कि प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलते ही कड़ी कानूनी कार्रवाई और भारी जुमार्ना लगाया जाएगा। 60 दिन गुजरने के बाद भी फेल मिले 6 सैंपलों पर पेनल्टी का निर्धारण नहीं हुआ, न ही किसी बड़े सिंडिकेट का लाइसेंस निरस्त किया गया। विभागीय कार्यशैली को देखते हुए साफ है कि इन नमूनों की जांच रिपोर्ट अब होली बीतने के बाद ही आएगी। जब तक प्रयोगशालाओं से मिलावट की आधिकारिक पुष्टि होगी, तब तक बनारसी क्विंटलों संदिग्ध और मिलावटी मिठाइयां डकार चुके होंगे। नतीजे आने तक खप जाती है पूरी मिठाई खाद्य नमूनों को जांच के लिए राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला (लखनऊ) भेजा जाता है। तय मानकों के अनुसार रिपोर्ट 14 से 30 दिनों के भीतर आ जानी चाहिए, लेकिन बनारस में महीनों फाइलें धूल फांकती हैं। जब नतीजे आते हैं, तब तक संबंधित बैच का सारा माल बिक चुका होता है और लोग पेट की बीमारियों का शिकार बन चुके होते हैं। यदि जांच रिपोर्ट समय पर नहीं आती और जुमार्ना तय करने में महीनों बीतते हैं, तो इस कागजी छापेमारी का खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को अपनी सेहत गंवाकर भुगतना पड़ता है। दूध से ज्यादा पनीर में मिलावट का खेल 6 माह में 39 सैंपल फेल, 21.52 लाख लगा जुमार्ना खाद्य विभाग की जांच में पिछले छह महीनों में दूध से कहीं ज्यादा पनीर में मिलावट मिली। मानकों पर खरे न उतरने के कारण अकेले पनीर के 39 सैंपल फेल हुए, जिन पर प्रशासन ने कुल 21.52 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है। जांच में तेल, चायपत्ती और हल्दी जैसे रोजमर्रा के सामान भी सिंथेटिक और मिलावटी पाए गए हैं। आम जनता का आरोप है कि विभाग केवल त्योहारों पर ही औपचारिकता निभाता है। जो भी सैंपल जांच में फेल हुए हैं, उनके लिए एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। कोर्ट की कार्यवाही में ही इन पर जुमार्ना लगाया जाएगा। नकली मिठाइयों, मावा व खोया की ऐसे करें पहचान मावे में आयोडीन की 2-3 बूंदें डालें, अगर रंग नीला या जामुनी हो जाए, तो उसमें स्टार्च या मैदा मिला है। असली मावे को हथेली पर मसलने पर घी की खुशबू आती है और यह दानेदार लगता है, जबकि मिलावटी मावा चिपचिपा होता है। वर्क को आग में जलाने पर असली चांदी की छोटी गेंद बन जाती है, जबकि मिलावटी एल्युमिनियम काला पड़ जाता है। असली वर्क उंगलियों पर चिपकता नहीं और रगड़ने पर गायब हो जाता है। एल्युमिनियम वर्क उंगलियों पर ग्रे रंग छोड़ता है। बहुत ज्यादा गहरे या चमकीले रंग वाली मिठाइयों से बचें, क्योंकि इनमें खतरनाक केमिकल रंगों की मिलावट हो सकती है।

पूर्वांचल स्टार्टअप संवाद में जुटेंगे 17 विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यपाल भी करेंगी शिरकत



अनप्लग इंडिया

प्रयागराज। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) विश्वविद्यालय और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के तहत चार नवंबर को पूर्वांचल स्टार्टअप संवाद-2026 का आयोजन किया जाएगा। इसमें 17 विश्वविद्यालयों के कुलपति और 100 से अधिक विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें 50 से अधिक स्टार्टअप एक्सपो में अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। स्टार्टअप संवाद के दौरान प्रदर्शनी के साथ तीन तकनीकी सत्र, एक पैनल डिस्कशन और एक गोलमेज बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें पूर्वांचल के विश्वविद्यालयों से जुड़े स्टार्टअप और नवाचारों पर चर्चा होगी। इसके अलावा, प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित शैक्षणिक सुविधाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। इनमें दो कॉन्फ्रेंस कक्ष, दो सेमिनार कक्ष, फिटनेस स्टूडियो और आयुर्वेद संग्रहालय शामिल हैं। इसका लोकार्पण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। आयोजन में प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के 100 से अधिक प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी भाग लेंगे। विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर से 100 से अधिक शिक्षक और 300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं, एकेटीयू से संबद्ध महाविद्यालयों के 100 से अधिक शिक्षक और विद्यार्थी भी संवाद का हिस्सा बनेंगे।

आईएमए का वार्षिकोत्सव: बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टर सम्मानित, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से यादगार बनाया पल

अनप्लग इंडिया



वाराणसी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) बनारस शाखा का 108वां वार्षिकोत्सव रविवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया गया। इस दौरान जहां चिकित्सकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। वहीं, चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि आईएमए मुख्यालय नई दिल्ली से निर्वाचित महासचिव डॉ. केएम अबुल हसन ने कहा कि आमजन को आईएमए की सेवाओं का लाभ दिलाकर शाखा को नई पहचान दिलाना सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए आगे आने की जरूरत है। गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों ने बनारस शाखा की ओर से रक्तदान, टीकाकरण, एंबुलेंस सेवा सहित अन्य सेवाओं की सराहना करते हुए पदाधिकारियों को बधाई दी। विशिष्ट अतिथि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर शरद अग्रवाल ने कहा कि नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ही लोगों को आईएमए की सेवाओं से परिचित कराते रहने की बात कही।
डॉ. आनंद प्रकाश ने भी सेवाओं की सराहना की। आईएमए अध्यक्ष डॉ. अनुराग टंडन, सचिव डॉ. अरुण कुमार त्रिपाठी ने इस दौरान शाखा की उपलब्धियों के साथ ही आगामी कार्ययोजना की भी जानकारी दी।
इस दौरान शाखा के अध्यक्ष निर्वाचित डॉ. मनोज कुमार श्रीवास्तव, डॉ. आलोक भारद्वाज, डॉ.अजीत सैगल, डॉ. मुमताज अंसारी, डॉ.एसपी सिंह, डॉ. शालिनी टंडन के साथ ही रामकुमार गुप्ता, सरदार सिंह, संदीप मौजूद रहे।

छोटी बहन की शादी से पहले तेज रफ्तार वाहन ने छीन लिया भाई, मचा कोहराम

अनप्लग इंडिया



कानपुर। हनुमंत विहार में रविवार देर रात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से अभय सचान (23) की मौत हो गई। वह काम खत्म कर पैदल घर लौट रहा था। नौबस्ता चौराहे के पास पीछे से आए वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में हैलट में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद मजदूरी कर मां और तीन बहनों की जिम्मेदारी उठा रहे अभय की मौत से परिवार बेसहारा हो गया। छोटी बहन कीर्ति की 20 नवंबर को शादी होनी है। जिस भाई के हाथों बहन की विदाई होनी थी, वही अब दुनिया में नहीं रहा। बाबा नगर स्थित चतुर्वेदी बिल्डिंग निवासी अभय के पिता की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। मां ऊषा गृहिणी हैं। तीन बहनों में बड़ी की शादी हो चुकी है, जबकि कीर्ति की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में तय है। एक बहन अभी पढ़ाई कर रही है। पिता के जाने के बाद अभय ने टाइल्स और पत्थर लगाने का काम संभाला और मेहनत-मजदूरी कर परिवार का खर्च उठाने लगा। परिजन के मुताबिक, रविवार देर रात साइट पर काम खत्म करने के बाद अभय पैदल घर लौट रहा था। नौबस्ता चौराहे के पास पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सड़क पर गंभीर हालत में पड़े अभय को राहगीरों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसे निजी अस्पताल ले गई। मोबाइल से परिजनों को सूचना दी गई। परिजन पहुंचे तो डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर उसे हैलट रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।अभय की मौत से मां ऊषा बदहवास हैं। छोटी बहन कीर्ति भाई का शव देखकर बेसुध हो गई। वह बिलखते हुए कहती रही कि पापा के जाने के बाद भाई ही परिवार का सहारा था। अब घर कौन चलाएगा, मां की देखभाल कौन करेगा और शादी के बाद उसे विदा कौन करेगा। जिस घर में कुछ दिन बाद शादी की खुशियां गूंजनी थीं, वहां अब भाई की मौत का मातम है। हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। टक्कर मारने वाले वाहन और चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।

कुशीनगर में वैन और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, छह लोगों की दर्दनाक मौत, किशोर गंभीर

अनप्लग इंडिया



कुशीनगर। हाटा कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। पेट्रोल पंप के पास वैन और ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह दुर्घटना देर रात उस समय हुई जब सभी लोग तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।
पुलिस ने घायल किशोर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हादसे के शिकार लोग कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भलुही गांव के निवासी वैन में सवार थे। प्रधान प्रतिनिधि कन्हैया प्रसाद (40) भी इनमें शामिल थे। उनके पिता रामबेलास (65) भी वैन में थे। राममिलन (35), आयुष (12), मृदुल मिश्रा (37) और रंजय गुप्ता (35) भी साथ थे। मिथिलेश गुप्ता (22) भी इस समूह का हिस्सा थे। वैन में सवार इन सात लोगों में से छह की मौत हो गई। राममिलन का 17 वर्षीय पुत्र आर्यन गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिलक समारोह से वापसी सभी लोग देवराज पिपरा में एक रिश्तेदार के तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से देर रात वे अपने गांव लौट रहे थे। हाटा कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास यह दुखद घटना हुई। सामने से आ रहे एक ट्रेलर से उनकी वैन टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस की कार्रवाई और जांच हादसे की सूचना मिलते ही भलुही गांव से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने और शवों को भेजने का काम किया गया।

सपा पर योगी का तीखा हमला: बोले- यूपी के लिए श्राप, सत्ता में आते ही मचाती है तबाही; कारसेवकों पर चलवाई थी गोली

अनप्लग इंडिया



गोंडा। यूपी के गोंडा में गौरा विधानसभा के तेजपुर में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कहा कि सपा प्रदेश के लिए श्राप है। जब-जब वह सत्ता में आई, तबाही लेकर आई। पहले प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू होते थे, त्योहारों से पहले ही लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती थी। आज उत्तर प्रदेश दंगा और कर्फ्यू से मुक्त है। मुख्यमंत्री ने दो नवंबर 1990 को अयोध्या में रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर हुई गोलीबारी का जिक्र करते हुए तत्कालीन सपा सरकार को निशाने पर लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो नवंबर 1990 को अयोध्या में तत्कालीन सरकार ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। आज भाजपा सरकार रामभक्तों पर फूलों की वर्षा कर रही है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पहले दुर्गा पूजा के पंडालों और धार्मिक आयोजनों को लेकर विवाद खड़े किए जाते थे। देवीपाटन मंडल में दुर्गा पूजा की अनुमति तक नहीं मिलती थी। कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाने की कोशिश होती थी। अब नवरात्र और कांवड़ यात्रा जैसे आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहे हैं।
गरीबों और युवाओं के हक पर डाका डालने का आरोप मुख्यमंत्री ने सपा सरकार पर गरीबों के हितों की अनदेखी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा कि उस समय गरीबों के बच्चों की कोई कीमत नहीं थी। गोंडा, बलरामपुर और बहराइच में अज्ञात बीमारी से बच्चों की मौतों के मामले सामने आते थे। स्वास्थ्य विभाग से पूछने पर भी बीमारी का पता नहीं चलता था। पिछली सरकार में गरीबों के हक पर डाका डाला जाता था और युवाओं के रोजगार के अवसरों के साथ खिलवाड़ होता था। उन्होंने 2016 के स्वच्छता सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि उस समय गोंडा की गिनती देश के सबसे गंदे शहरों में होती थी। सपा शासन में हुए खाद्यान्न घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मौजूदा सरकार में राशन, रसोई गैस और आयुष्मान जैसी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। दंगाइयों को संरक्षण देने वालों को बख्शेंगे नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दंगा करने वालों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। अब कोई भी कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में मजबूत कानून-व्यवस्था के कारण निवेश का माहौल बना है। गोंडा में करीब तीन हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से सैकड़ों करोड़ की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में गोंडा जिले के लिए 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। देवीपाटन मंडल में करीब 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम हुआ है। पहले गोंडा के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी सपना थी, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है।

फिल्मों में काम दिलाने पर सैफ को लेकर बोलीं सारा अली खान



अभिनेत्री सारा अली खान अपनी फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने अपने पारिवारिक बैकग्राउंड को लेकर चल रही चर्चाओं पर बात की है। उन्होंने साफ किया कि उनके पिता और अभिनेता सैफ अली खान ने कभी भी उनके फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत नहीं की। उन्होंने एक मशहूर फिल्मी परिवार से आने के दोहरे पहलुओं पर चर्चा की।

पिता ने नहीं की सिफारिश

फिल्मफेयर से बातचीत में सारा ने कहा, 'मैं अपनी सिंगल मदर के साथ रहती हूं। मेरे पिता कभी किसी ऑफिस में जाकर मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत नहीं करते थे और न ही उन्होंने कभी किसी से मुझे अपनी फिल्मों में लेने की गुजारिश की। जब मुझे 'केदारनाथ' के समय कोई परेशानी हुई, तो मैंने उसे खुद ही सुलझाया। उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था। यह एक दोधारी तलवार की तरह है, क्योंकि इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा है।'

पारिवारिक पृष्ठभूमि का मिला फायदा

सारा ने माना कि अपने परिवार की वजह से उन्हें कुछ खास फायदे जरूर मिले हैं। उन्होंने कहा कि वह इतनी नासमझ या भ्रम में नहीं हैं कि उन मौकों को न देख सकें जो उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से उन्हें शुरुआत में मिल गए थे। हालांकि, उनका यह भी मानना है कि लगातार होने वाली जांच-परख की वजह से उन पर उम्मीदों का बोझ डाल दिया जाता है।

नेपोटिज्म पर क्या बोलीं सारा

सारा ने इस बात पर जोर दिया कि 'नेपोटिज्म' (भाई-भतीजावाद) शब्द को पूरी तरह से नकारात्मक बना दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह उन स्टार किड्स जैसे कि खुद सारा, जाह्नवी कपूर और अनन्या पांडे की कड़ी मेहनत को कम करके आंकता है, जबकि अपने माता-पिता को चुनने में इन कलाकारों का कोई हाथ नहीं था।

इंडस्ट्री में टिके रहने पर बोलीं सारा

सारा ने यह तो माना कि उन्हें और उनके साथियों को ऐसे शानदार डेब्यू मिले, जिनके लिए कई नए कलाकार तरसते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर खुद को साबित करने का बोझ हमेशा उन्हीं के कंधों पर क्यों रहता है? हिंदी सिनेमा में अपने आठ साल के सफर के बाद, उनका कहना है कि अब उन्हें बार-बार यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वह इंडस्ट्री में अपनी जगह की हकदार हैं। सारा ने कहा कि भले ही शुरुआत में मिलने वाले फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद लेना और स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है।

सारा अली खान का वर्क फ्रंट

सारा हाल ही में निर्देशक आकाश ए. कौशिक की फिल्म 'उड़ता तीर' में नजर आई। फिल्म में आयुष्मान खुराना, राहुल बोस, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला, संदीप आनंद और अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म छह दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 26.87 करोड़ रुपये कमाए हैं।



शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 1233, निफ्टी 387 अंक उछला

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दूनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी होने से आई हैं। आज कारोबार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, एनटीपीसी, मारुति, बजाज फाइनेंस के शेयरों में उछाल आया जिससे बाजार धारणा मजबूत हुई। सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं आईटी स्टॉक्स में गिरावट रही। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1233.25 अंकों की तेजी के साथ ही 75,692.78 अंकों पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी 387.70 अंक उछलकर 23,440.80 अंकों पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स की 30 में से 23 कंपनियों के शेयर ही बढ़त पर बंद हुए और शेष सभी 7 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 50 की 50 में से 38 कंपनियों के शेयर तेजी के साथ बंद हुए और बाकी की सभी 12 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज सबसे अधिक 11.64 फीसदी की तेजी रही। इसके अलावा टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और एसबीआई के शेयरों में भी तेजी रही।

सेंसेक्स की अन्य कंपनियों की बात करें तो आज टाटा स्टील , अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई , एनटीपीसी 2.37, मारुति सुजुकी , बजाज फाइनेंस , एलएंडटी , बीईएल , हिंदुस्तान यूनिलीवर , एशियन पेंट्स , बजाज फिनसर्व , इंडिगो तेजी के साथ बंद हुए। वहीं वहीं दूसरी ओर, आज कोटक महिंद्रा बैंक , आईसीआईसीआई बैंक , सन फार्मा , एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और टीसीएस के शेयरों में गिरावट रही। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की तेज शुरुआत हुई।



सुबह सेंसेक्स अपने पिछले बंद भाव 74,459.53 के मुकाबले 75,178.24 पर खुला, जो 718.71 अंकों की शानदार छलांग थी। वहीं निफ्टी ने अपने पिछले बंद भाव 23,053.10 से 169.2 अंक उछलकर 23,222.30 पर सत्र की शुरुआत की

रुपया गिरावट के साथ बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सोमवार को 9 पैसे की गिरावट के साथ ही 94.86 पर बंद हुआ।



आज सबह शुरुआती कारोबार में रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.97 पर पहुंच गया। विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग से घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि हालांकि घरेलू बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी से रुपये को निचले स्तर पर थोड़ा समर्थन मिला।

वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.90 प्रति डॉलर पर खुला। फिर फिसलकर 94.97 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 21 पैसे की गिरावट है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.76 पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 109.95 पर पहुंच गया।

भारत बनाम न्यूजीलैंड... गंभीर बोले-टी-20 टीम के प्रदर्शन पर गर्व

नई दील्ली। भारत ने न्यूजीलैंड को 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 3-2 से हराया। सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, मेरी डिक्शनरी और डायरेक्टरी में डर नाम का कोई शब्द नहीं है। गंभीर ने पहले मैच का उदाहरण देते हुए खिलाड़ियों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि टीम ने 15 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद सिर्फ एक अभ्यास सत्र किया था, इसके बावजूद मुकाबला जीत लिया। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि गेंदबाजी और फील्डिंग बेहतर हो सकती थी। वहीं न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को सीरीज का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने पांच मैचों में 341 रन बनाए।

ध्यान अब वनडे सीरीज पर: अय्यर - अय्यर के मुताबिक, न्यूजीलैंड में खेलने के दौरान खिलाड़ियों को अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आसमान में साफ रोशनी और मैदान पर अंधेरे जैसी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियां भारत में आमतौर पर देखने को नहीं मिलतीं। कप्तान ने यह भी कहा कि टीम इन कमियों पर चर्चा करेगी। हालांकि, उनका ध्यान अब वनडे सीरीज पर है और खिलाड़ी अच्छे मूड में हैं।

ऋषभ पंत की चोट पर गंभीर के पास अपडेट नहीं - प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर से ऋषभ पंत की उपलब्धता को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास पंत की चोट को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं है।



थकान के बावजूद जीत हासिल की- गंभीर ने कहा, विदेशी परिस्थितियों में खेलते समय टीम को मुश्किल हालात से घबराना नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को लंबी यात्रा और कम अभ्यास का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पहले मैच में जीत हासिल करना आसान नहीं था। गंभीर ने इसी प्रदर्शन को टीम की मानसिक मजबूती का उदाहरण बताया। सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों में भारत ने लगातार जीत दर्ज की। इसके बाद न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए आखिरी दोनों मैच अपने नाम किए।

सीरीज का नतीजा उलटा भी हो सकता था- सैंटनर: न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने माना कि सीरीज काफी करीबी रही। उनके मुताबिक, शुरुआती दो मुकाबलों में कुछ ऐसे मौके आए, जिन्हें न्यूजीलैंड भुना सकता था। अगर टीम उन मौकों पर बेहतर प्रदर्शन करती, तो सीरीज का नतीजा भारत के बजाय न्यूजीलैंड के पक्ष में भी हो सकता था। सैंटनर ने गेंदबाजी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आखिरी दो मैचों में गेंदबाजों ने परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदली। तेज गेंदबाजों ने यॉर्कर, वाइड गेंदों और सही लेंथ का इस्तेमाल किया।



एंटोनेली बने सबसे कम उम्र के एफ-1 चैंपियन

नई दिल्ली। किमी एंटोनेली नेइतिहास रचते हुए फॉर्मूला वन के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 20 वर्षीय मर्सिडीज ड्राइवर ने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टापेन और लुईस हैमिल्टन के बाद तीसरे स्थान पर रहकर यह उपलब्धि प्राप्त की।

किमी, जो फॉर्मूला वन रेसिंग में अपने दूसरे ही सीजन में हैं, ने सेबेस्टियन वेटेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2010 में अपनी चार ड्राइवर चैंपियनशिप में से पहली चैंपियनशिप जीतने के समय 23 साल और 133 दिन के थे। अपनी उपलब्धि की वास्तविकता को समझते हुए किमी अपने आँसू रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

टीम रेडियो पर, नव-ताजपोश विश्व चैंपियन पहले तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मर्सिडीज को अपने सपने को साकार करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। 'हमने कर दिखाया! हमने कर दिखाया!' उसे हंसते-हंसते आंसुओं के साथ कहते हुए सुना गया। इसके बाद जो जश्न मनाया गया, वह इस अवसर के अनुरूप ही था।

पोडियम पर एंटोनेली अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे, तभी वर्स्टापेन और हैमिल्टन ने भी उनका साथ दिया और नव-प्रतिभाशाली चैंपियन को हवा में उठा लिया। यह एक यादगार दृश्य था: खेल के दो महानतम ड्राइवर फॉर्मूला वन चैंपियन की नई पीढ़ी के आगमन का जश्न मना रहे थे। मैं भविष्य में और अधिक मुकाबलों के लिए उत्सुक हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'यह तो बस शुरुआत है।' एंटोनेली के लिए, यह सात साल के कार्टिंग के शौकीन से लेकर मोटरस्पोर्ट के शिखर तक की एक उल्लेखनीय यात्रा की परिणति थी।

मर्सिडीज टीम के प्रमुख टोटो वोल्फ के लिए भी, 2025 सीज़न से पहले हैमिल्टन की जगह 18 वर्षीय खिलाड़ी को मौका देने के उनके महत्वपूर्ण जोखिम भरे फैसले की पुष्टि का क्षण था।

उनके बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक मोंज़ा में देखने को मिला, जहाँ उन्होंने ग्रिड पर 19वें स्थान से शुरुआत करने के बावजूद अपने घरेलू ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की।

सिंधू ने जीता हाइलो ओपन का खिताब

जर्मनी: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने एक बार फिर अपने शानदार खेल से देश का नाम रोशन किया है। सिंधु ने जर्मनी में खेले गए हाइलो ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में डेनमार्क की लाइन केजर्सफेल्ट को सीधे गेमों में 21-12, 21-14 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सिंधु ने मौजूदा सीजन का अपना दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है।

पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहीं सिंधु - सिंधु का हाइलो ओपन में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। उन्होंने फाइनल तक के सफर में एक भी गेम नहीं गंवाया। अपने अभियान की शुरुआत उन्होंने भारतीय खिलाड़ी प्रकृति भरत को हराकर की। इसके बाद फ्रांस की रोजी ओक्टाविया पंकासारी और जर्मनी की अमाली शुल्ज को मात देकर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उन्होंने भारत की ही अनमोल खरब को 21-13, 21-16 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया।

फाइनल जीतकर बनीं चैंपियन

पीवी सिंधु ने फाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पहला गेम महज 17 मिनट में 21-12 से जीतकर डेनमार्क की खिलाड़ी पर दबाव बना दिया। इसके बाद दूसरे गेम में भी सिंधु ने अपनी लय बरकरार रखी और 21-14 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय शटलर ने यह फाइनल केवल 39 मिनट में जीतकर शानदार अंदाज में खिताब पर कब्जा किया।

जापान ओपन के बाद अब हाइलो ओपन पर कब्जा

पीवी सिंधु के लिए यह साल खिताब के लिहाज से शानदार रहा है। उन्होंने जुलाई में जापान ओपन 2026 के फाइनल में जापान की तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को हराकर खिताब जीता था। अब हाइलो ओपन जीतकर उन्होंने इस सीजन का दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम कर लिया है।

विश्व टूर फाइनल्स की राह हुई मजबूत

हाइलो ओपन का खिताब जीतने के साथ ही सिंधू को 9200 रैंकिंग अंक मिले हैं। इससे साल के आखिर में होने वाले विश्व टूर फाइनल्स में जगह बनाने की उनकी उम्मीदों को मजबूती मिली है। दुनिया की आठवें नंबर की भारतीय खिलाड़ी के लिए यह जीत सीजन के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। सिंधू के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने का दम रखती हैं।



चेक ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट... सेंथिलकुमार ने फाइनल में बनाई जगह

ब्रनो। भारत के वेलावन सेंथिलकुमार ने ब्रनो में चल रहे चेक ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। 35,000 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस पीएसए कॉपर-लेवल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी और विश्व नंबर 32 ऑगस्ट डुसॉर्ड को हराया। सेंथिलकुमार ने सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी को 11-7, 12-10, 11-1 से मात दी। चौथे वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी अब फाइनल में स्कॉटलैंड के ग्रेग लोबन (जो शीर्ष वरीयता प्राप्त हैं और विश्व रैंकिंग में 31वें नंबर पर हैं) का सामना करेंगे। सेंथिलकुमार इस सीजन में अपना दूसरा खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त लोबन ने फ्रांस के तौफिक मेखल्फी को 11-9, 11-5, 11-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले, सेंथिलकुमार ने अर्जेंटीना के जेरेमियास अजाना को 11-3, 11-8, 11-7 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। पहले गेम में भारतीय खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के जेरेमियास अजाना को आसानी से 11-3 से हराया। इसके बाद, रैलियां तेज, कड़ी और रोमांचक हो गई थीं। सेंथिलकुमार ने कोर्ट के अगले हिस्से में बेहतरीन खेल दिखाते हुए बाकी गेम 11-8 और 11-7 से अपने नाम किया था। भारतीय खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के विश्व नंबर 64 और आठवें वरीयता प्राप्त जेरेमियास अजाना को 11-3, 11-8, 11-7 से हराया था। इससे पहले, टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में उन्हें 'बाय' (सीधे अगले दौर में प्रवेश) मिला था, और दूसरे दौर में उन्होंने ब्राजील के डिएगो गोब्बी को 11-4, 11-7,



संक्षिप्त समाचार

ईरान समझौता करना चाहता है, बातचीत सही दिशा में, सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला : ट्रंप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ ईरान समझौता करना चाहता है और दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी चल रही है। हालांकि, उन्होंने ईरान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह समझौता करने के बाद पीछे हट जाता है। फ्लोरिडा में हैलोवीन पार्टी के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या वह वास्तव में किसी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ''वे समझौता करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि वे ऐसा कर पाते हैं या नहीं।'' ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत भरोसेमंद नहीं है। वह पहले समझौता करता है और फिर उससे पीछे हट जाता है। इसके बावजूद अमेरिका बातचीत को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने कतर की मध्यस्थता में चल रही बातचीत की समयसीमा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि अमेरिका को कोई खास जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि 'अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में ईरान की नौसेना, वायुसेना और हथियार निर्माण की क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 'पिकएक्स माउंटेन' को निशाना बनाने की धमकी भी दोहराई। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो इस ठिकाने पर बहुत तेजी से हमला कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि इस पहाड़ी के नीचे ईरान का परमाणु ठिकाना मौजूद है। ईरान पर दोबारा सैन्य हमले का आदेश देने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने सवाल को 'बेवकूफाना' बताया। उन्होंने कहा, ''मान लीजिए कि मैंने ऐसा करने का फैसला किया, तो क्या मैं आपको पहले बता दूंगा? मैं यह नहीं बता सकता।

घड़ी के शीशे बनाने वाली झोउ छुनफेई अब चीन की सबसे अमीर महिला बनीं

बीजिंग, एजेंसी। चीन की एक महिला ने फैक्टरी में काम करने से लेकर देश की सबसे अमीर महिला बनने तक का सफर तय किया है। 56 साल की झोउ छुनफेई ने किशोरावस्था में ही स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने एक फैक्टरी में काम शुरू किया। आज वह ग्लास बनाने वाली कंपनी लेंस टेक्नोलॉजी की संस्थापक हैं। उनकी अनुमानित संपत्ति 1.27 लाख करोड़ युआन यानी करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये है। 28 अक्तूबर को जारी हुरुन की 2026 की चीन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में झोउ ने फिर पहला स्थान हासिल किया है। पिछले एक साल में उनकी संपत्ति 15% बढ़ी है। एपल के आईफोन से बदली किस्मत झोउ को बड़ी कामयाबी 2007 में मिली, जब उसे एपल के शुरुआती आईफोन के लिए ग्लास कवर बनाने का ऑर्डर मिला। इसके बाद एपल का कारोबार लेंस की कमाई का बड़ा स्रोत बन गया। हुरुन एक वैश्विक शोध और प्रकाशन संस्थान है, जो 1999 से चीन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी कर रहा है। यह सूची चीन के सबसे अमीर लोगों की समग्र सूची से अलग है। इसमें परिवारों या दंपतियों की संयुक्त संपत्ति के बजाय महिलाओं की व्यक्तिगत संपत्ति का आकलन किया जाता है, जिसे परिवार की संपत्ति से अलग पहचाना जा सके।

समुद्र में 352किलोमीटर की गहराई पर केंद्र; सुनामी का अलर्ट नहीं

टोक्यो, एजेंसी। जापान के मी प्रांत के तट के पास रविवार सुबह 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप का केंद्र भूकंप का केंद्र मी प्रांत की राजधानी त्सु से करीब 110 किलोमीटर दक्षिण में था। त्सु की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा है। भूकंप समुद्र में जमीन से 352 किलोमीटर की गहराई में आया। भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। फिलहाल किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर की वेबसाइट पर लोगों ने बताया कि झटके काफी देर तक महसूस हुए। शुरुआत में हल्के झटके लगे, जो धीरे-धीरे तेज होते गए। जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। यह चार बड़े टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा है और प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' का हिस्सा है। हर साल यहां करीब 1500 भूकंप आते हैं, जिनमें से ज्यादातर हल्के होते हैं। जापान के नोटो द्वीप में 2024 में आए भूकंप में करीब 600 लोग मारे गए थे। 2011 में 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी ने 18 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी।

चिदंबरम का नितिन नवीन से सवाल- 3 करोड़ घुसपैठिए हैं कौन, क्यों काटे 13.30 करोड़ नाम?

-कांग्रेस नेता ने घुसपैठियों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की

नई दिल्ली , एजेंसी। देश में घुसपैठियों की संख्या और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के देश में तीन करोड़ घुसपैठिए होने के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल करते हुए सरकार से घुसपैठियों की पहचान सार्वजनिक करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की है।

चिदंबरम का सवाल है, कि भाजपा अध्यक्ष ने जिन तीन करोड़ घुसपैठियों की बात कही है, वे कौन हैं और क्या केंद्र तथा राज्य सरकारों ने उनकी पहचान कर ली है? यदि हरियाणा के लोगों को घुसपैठियों की जानकारी है तो राज्य सरकार उनके नाम सार्वजनिक कर कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसी के साथ ही चिदंबरम ने कहा, कोई भी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा



है, लेकिन उनकी पहचान और संख्या को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए। चिदंबरम ने सवाल किया है, यदि देश में तीन करोड़ घुसपैठिए हैं तो एसआईआर के दौरान 13.30 करोड़ नाम क्यों हटाए गए? क्या हटाए गए सभी नाम मृत लोगों के थे? उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपील के बाद दोबारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले लोगों का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, हटाए गए नामों में से 91 से 93 प्रतिशत लोगों ने अपील में सफलता हासिल की। उन्होंने पूछा कि क्या ये लोग भी घुसपैठिए थे?

कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप

दूसरी ओर, नितिन नवीन ने कांग्रेस पर चुनावी नतीजों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और केरल में जीत मिलने पर कांग्रेस लोकतंत्र को सही मानती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हारने पर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। नवीन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर केवल राजनीतिक मुद्दे खड़े कर रही है। उन्होंने बिहार में बूथ लेवल एजेंटों की मौजूदगी और शिकायतों का हवाला देते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए।

महादेव एप मामले में सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण: सीएम साय ने बताया बड़ी सफलता

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप घोटाले के कथित सरगना सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण को बड़ी सफलता बताया है। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उससे पूछताछ के बाद उन लोगों की पहचान सामने आएगी, जिन्हें इस अवैध सट्टा सिंडिकेट से प्रोटेक्शन मनी मिलता था। उन्होंने कार्रवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने चंद्राकर को ओमान से भारत वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीबीआई अधिकारियों ने बताया था कि एजेंसी ने छह हजार करोड़ रुपये के कथित महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप घोटाले के सिलसिले में चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कराया है। सीबीआई की टीम आरोपी चंद्राकर को भारत लेकर आई थी और सोमवार को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। चंद्राकर दो सीबीआई मामलों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में वांछित था, जिसमें पहले ही आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। उसके खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद सीबीआई और ईडी के औपचारिक अनुरोध पर प्रत्यर्पण संभव हो पाया। जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट में से एक था, जिसे भारत के बाहर से फ्रेंचाइजी पैनलों के जरिए संचालित किया जा रहा था।

राहुल गांधी खुद आज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती: सुधांशु त्रिवेदी

- राहुल के आने से पहले कांग्रेस कई राज्यों में शून्य

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में गलत नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाकर कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बीजेपी सांसद त्रिवेदी ने टिप्पणी करते हुए विपक्ष की उस प्रवृत्ति पर सवाल उठाया, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और बढ़ती राष्ट्रीय गौरव की भावना से खुश नहीं दिखते। बीजेपी सांसद त्रिवेदी ने कांग्रेस के कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओडिशा में बीते 25 वर्षों से, गुजरात में 1995 से और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 1990 के दशक से सत्ता से बाहर है। इन राज्यों में कुल 120 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी के सत्ता-विरोधी लहर (एंटी-इनकम्बेंसी) के दावे को खारिज कर कहा कि वास्तविकता इससे काफी अलग है।



बीजेपी त्रिवेदी ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि उनकी पार्टी, उनके राजनीति में आने से बहुत पहले ही, उन राज्यों में भी 10 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं थी जहाँ कुल 230 लोकसभा सीटें आती हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि कांग्रेस उन 230 सीटों में पहले से ही कमजोर थी, तब शेष 300 सीटों में से 272 जीतने की उम्मीद कैसे हो सकती थी? यह आंकड़ा कांग्रेस की वास्तविक स्थिति को दिखाता है और चुनावी परिणामों पर उनके गलत नैरेटिव को बेनकाब करता है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलएस) की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगाया। उन्होंने पूछा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया की निगरानी में उनकी क्या भूमिका थी। त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि जहां चुनाव आयोग सरकारी कर्मचारियों (बीएलओ) के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट करता है, वहीं राजनीतिक दल अपने बीएलओ नियुक्त करते हैं ताकि इस प्रक्रिया पर नज़र रखी जा सके। पूरे देश में, चुनाव आयोग द्वारा 12 लाख बीएलओ और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 22 लाख बीएलए नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी सांसद त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का मौजूदा रवैया न केवल तथ्यों से परे है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक गंभीर चुनौती भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे चुनावी प्रक्रियाओं पर गलत धारणाएं फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, पीएम मोदी की 18 मंडलों में होंगी रैलियां

बीजेपी के चाणय अमित शाह संभालने वाले हैं चुनावी रणनीति

लखनऊ, एजेंसी । उत्तरप्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अभी से तैयारियां तेज करने की रणनीति तैयार की है। दिवाली के बाद पार्टी प्रदेश में तीन स्तरों पर व्यापक चुनावी अभियान शुरू करने की तैयारी में है। नवंबर और दिसंबर के दौरान चलने वाले अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका होगी। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से काफी पहले प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करना है।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा की प्रस्तावित रणनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले है। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सभी 18 प्रशासनिक मंडलों में बड़ी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। इन रैलियों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने, मतदाताओं तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने और भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। पार्टी चाहती है कि उसका संदेश प्रदेश के हर प्रमुख क्षेत्र तक सीधे पहुंचे।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री शाह चुनावी रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों की कमान संभालने वाले है। उनके नेतृत्व में अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों में रैलियां तथा बूथ स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान होगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अभियान को गति देने वाले है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम, रैलियां और संगठनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी भी अभियान का महत्वपूर्ण चेहरा है। वह जिला स्तर पर रैलियां कर सभी विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे है। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद अभियान पूरी गति पकड़ सकता है। इसके लिए पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता और छोटी टीम को कम से कम 50 परिवारों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कार्यकर्ता घर-घर जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले है। इस चुनावी रणनीति में युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को भी विशेष महत्व दिया गया है। पार्टी इन मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने और सरकार की योजनाओं से जोड़ने पर जोर देगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जाएगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं को रैलियों, जनसभाओं और क्षेत्रीय कार्यक्रमों की तस्वीरें, वीडियो और अपडेट साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भाजपा की इस तीन स्तरीय रणनीति का मकसद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में संगठन को मजबूत करना और व्यापक जनसमर्थन जुटाना है।

सोनिया की लालू से मुलाकात, तेजस्वी ने कहा... चुनौतियों के लिए एकजुट हो विपक्ष

नई दिल्ली,एजेंसी। नई दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस दौरान राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने देशभर में विपक्षी दलों को एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया। यह मुलाकात दिल्ली स्थित लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती के आवास पर हुई। तेजस्वी ने बताया कि लालू यादव नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली आए हुए थे। रविवार को उनकी सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई थी और लालू प्रसाद के दिल्ली में होने की जानकारी मिलने पर सोनिया गांधी ने स्वयं उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद यह भेंट हुई। उन्होंने दोनों परिवारों के बीच दशकों पुराने मधुर संबंधों का जिक्र कर कहा कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद ने हमेशा एक-दूसरे के कठिन समय में सहयोग किया है। यह एक लंबे अंतराल के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात थी। तेजस्वी ने विपक्षी एकजुटता पर जोर देकर कहा कि केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में विपक्षी दलों को एक साथ आकर मजबूती से चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी विपक्षी दल एकजुट नहीं होते हैं, तब तक वर्तमान लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। उनका यह बयान विपक्षी इंडिया गठबंधन की मजबूती के प्रयासों के बीच आया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी, जिसमें कहा कि जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक विपक्ष चुप नहीं बैठेगा और उनका संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में हाल ही में हुई रैली को फ्लॉप बताने के दावों को खारिज कर तेजस्वी ने कहा कि विरोधी बेचैन और परेशान हैं, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र को कुचलकर उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। महाभारत की लड़ाई और कृष्ण के बारे में पूछने पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि पहले शकुनि को जान लीजिए।

'इस्राइल जनादेश: पीएम चुनने का विधेयक ला सकता है विपक्षी दल, बदू महिलाओं ने कैसे पलटा नेतन्याहू का चुनावी पासा?

यरूशलम, एजेंसी। उम्म खालिद फतून पिछले साल युद्ध पीड़ितों के लिए बने एक यहूदी-अरब सहायता केंद्र में स्वयंसेवा करके लौटीं तो उन्होंने देखा कि बुलडोजर अजारनुग गांव में उनके बेटे के घर को ढहा रहे थे। पुलिस की निगरानी में आई टीम ने घर पर बुलडोजर चलाने से पहले फर्नीचर या सोलर पैनल तक हटाने का मौका नहीं दिया। अब, इस हफ्ते जब फतून को मौका मिला तो उन्होंने अपनी नाराजगी का जवाब इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ मतदान करके दिया। उनका सीधा निशाना राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर थे जिन्होंने फलस्तीनी और अरब समुदाय के लोगों के घरों को व्यापक स्तर पर ढहाने का आदेश दिया था। फतून कहती हैं, बेन-



ग्विर को सत्ता से बाहर करना ही मेरा एकमात्र मकसद था। बदू समुदाय में ऐसा एक भी परिवार नहीं है जो हमारे खिलाफ उसके अभियानों से पीड़ित न हुआ हो। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले फतून ने बदू महिलाओं को उनके अधिकारों और राजनीतिक ताकत के प्रति जागरूक करने के लिए जमीनी स्तर पर बाकायादा अभियान शुरू किया। इसके शानदार नतीजे भी दिखे, और चुनाव में दक्षिणी नेगेव इलाके के कुछ बदू गांवों में मतदान प्रतिशत तीन गुना तक बढ़ गया।

हमें अपने हर वोट की ताकत झोंकनी होगी : अल-नश्मियात अभियान का नेतृत्व करने वाली वकील हनान अलसनाह ने कहा, वर्षों के हिंसक शासन ने इस रूढ़िवादी समुदाय में बदलाव का दरवाजा खोल दिया है। हमने महिलाओं से कहा कि भले सभी पुरुष वोट दें फिर भी समुदाय का आधा हिस्सा ही होंगे। आपको अपने हर वोट की ताकत चाहिए, क्योंकि बेन-ग्विर के पास बहुत ताकत है।

62% से 93% तक दर्ज की गई वोटिंग : बदू समुदाय इस्राइली संसद नेसेट में अरब पार्टियों को 19 सीटें दिलाकर किंगमेकर की भूमिका में ला दिया। बदू समुदाय में सबसे कम मतदान 62% रहा, जबकि सबसे ज्यादा मतदान 93% दर्ज किया गया। उनके उत्साह से ही रआम पार्टी को चुनावी अनुमानों से काफी अधिक सफलता मिली। इस्राइल में सरकार गठन में राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए विपक्षी गुट अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहे बिना अल्पमत सरकार बनाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री चुनने से संबंधित विधेयक लाने पर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव लागू होने पर मतदाता सरकार से अलग सीधे पीएम पद के लिए वोट डाल सकेंगे।

ट्रम्प की नेतन्याहू से फोन पर बात:बाद में बोले- ईरान के 1-2 ठिकाने और उड़ाना बाकी



वॉशिंगटन डीसी/तेल अवीव, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शनिवार को फोन पर बातचीत की। यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी। इसके बाद रविवार को ट्रम्प ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े एक या दो ठिकाने अभी उड़ाना बाकी हैं। इनमें पिकैक्स माउंटेन भी शामिल है। वहीं, अमेरिकी न्यूज चैनल एमएस नाउ ने बताया कि वॉशिंगटन ने खाड़ी देशों को ईरान पर नए हमलों के लिए तैयार रहने को कहा है। ये हमले 4 नवंबर से शुरू हो सकते हैं। यह तारीख अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के अगले दिन की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने हाल के हफ्तों में पश्चिम एशिया में हवाई सुरक्षा सिस्टम, गोला-बारूद और सैन्य उपकरणों की तैनाती बढ़ाई है। साथ ही, उसने अपने सैनिकों और सैन्य सामान को उन ठिकानों से दूसरी जगह भेजना शुरू कर दिया है, जहां ईरान हमला कर सकता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का मानना है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इजराइल ने हमले की तैयारी कर ली है। इजराइली न्यूज चैनल चैनल 12 के मुताबिक, पिछले हफ्ते अमेरिका के 10 सैन्य मालवाहक विमान इजराइल पहुंचे थे। इनमें हवाई हमलों से बचाव के लिए जरूरी उपकरण होने की बात कही जा रही है। इनका इस्तेमाल क्षेत्र में अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। इससे पहले, दो हफ्ते पहले इजराइल के कई लड़ाकू विमानों ने ईरान की सीमा तक उड़ान भरी थी और फिर वापस लौट आए थे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा था। ट्रम्प इन दिनों 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के आखिरी प्रचार अभियान में जुटे हैं। इन चुनावों में अमेरिकी संसद के लिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ईरान के साथ युद्ध और अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतें रिपब्लिकन पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। ट्रम्प चुनाव के आखिरी दिनों में अपनी पार्टी के समर्थन को बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तारीख आगे बढ़ाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान भी अमेरिकी चुनाव से पहले बातचीत को जानबूझकर लंबा खींच रहा है।

'एस.जयशंकर: 'क्वाड देशों में चुनने की आजादी जरूरी', सप्लाई चेन और आर्थिक सुरक्षा पर और क्या बोले विदेश मंत्री?

अटलांटा , एजेंसी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को क्वाड के लिए 'चुनने की स्वतंत्रता', मजबूत सप्लाई चेन और गैर-बाजार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई को मुख्य प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही, उन्होंने इस समूह के एजेंडे के लिए एक अधिक समकालीन और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। अटलांटा में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में जयशंकर ने उन प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया, जिन पर उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ चर्चा की थी।

जयशंकर ने क्या कहा : समूह की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना, समृद्धि को बढ़ावा देना और पसंद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हमारी निरंतर प्रतिबद्धताएं हैं।' उन्होंने टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत सप्लाई चेन बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

गैर-बाजार प्रथाओं का भी किया जिक्र : जयशंकर ने चर्चा के दौरान उठाई गई प्राथमिकताओं में इंडो-पैसिफिक में गैर-बाजार



प्रथाओं का मुकाबला करने और बढ़ते आर्थिक दबावों को भी शामिल किया। हालांकि, उनकी पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया गया और न ही यह बताया गया कि किन विशिष्ट प्रथाओं की बात हो रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, उन्होंने आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण से जुड़े मौजूदा समझौतों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि मजबूती बढ़ाई जा सके और शांति व स्थिरता को समर्थन मिले।

एआई को लेकर क्या चर्चा हुई : मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की इच्छा जताई। इसमें 'क्वाड एआई एक्सेलेरेटर' के माध्यम से दी जाने वाली मदद भी शामिल है। विज्ञप्ति में सुपर इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया गया है, जिसके साथ एक फुटनोट में स्पष्ट किया गया है कि यह शब्द भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। मंत्रियों ने भारत और आसियान देशों में कचरे से महत्वपूर्ण खनिज निकालने की सुविधाओं के लिए वाशिंगटन द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के वादे का स्वागत किया। यह राशि केवल भारत के लिए नहीं है। ये चारों साझेदार देश, इलेक्ट्रॉनिक कचरे और कबाड़ से खनिज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम की जा सके। वे रीसाइकल होने वाली सामग्रियों को एक देश से दूसरे देश भेजने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के तरीकों पर भी विचार करेंगे। समुद्री सहयोग के तहत, चारों देशों के प्रतिनिधियों ने 25 सितंबर से 7 अक्तूबर के बीच चेन्नई से पर्थ तक भारतीय तटरक्षक बल के एक गश्ती जहाज पर यात्रा की। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इनका सहयोग समुद्री और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियों, तथा मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत ने जी20 को बताया कि ऊर्जा आपूर्ति का राजनीतिकरण बहुत हानिकारक है।

नेक्सटऐज मीडिया एंड कंलटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, प्रकाशक, संपादक अनीता यादव द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी मेसेर्स साईं प्रिंटिंग प्रेस डी-85 सेक्टर-06 201301 से मुद्रित कराकर 962 सरफाबाद सेक्टर-73, नोएडा-201304 से प्रकाशित किया,
प्रधान संपादक : रिंकू यादव संपादक : अनीता यादव PRGI No. UPHIN/26/A8255 Ph. : 4403949, Email : unplugindia26@gmail.com